समवेत शिखर

36 वां स्थापना वर्ष

वर्ष-36 अंक-278 | रायपुर, बुधवार 25 फरवरी 2026 | पृष्ठ : 08, मूल्य : 2.50 रुपए, ई-पेपर: samvetshikhar.com

बजट 2026-27 : विकसित छत्तीसगढ़ के लिए 'संकल्प'

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया

- 20,400 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान
- एजुकेशन, इंडस्ट्री और कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश
- बस्तर के विकास का खींचा बड़ा खाका
- स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली
- किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा
- महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 फीसदी छूट
- 'रानी दुर्गावती योजना' से बालिकाओं को 18 वर्ष होने पर 1.50 लाख देने की घोषणा
- कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना
- बजट में 11 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान
- 5 मुख्यमंत्री मिशन की घोषणा

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर 'संकल्प' थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में बस्तर और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार का बड़ा खाका खींचा।

2 हजार करोड़ के घाटे वाले इस बजट में एक तरफ जहां 1 लाख 43 हजार करोड़ रुपए आय का अनुमान जताया गया है, तो वहीं दूसरी ओर 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। इस तरह से यह 20,400 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.87 प्रतिशत है।

प्राप्तियों की बात करें तो 1 लाख 43 हजार करोड़ रुपए में से राज्य के स्वयं के संसाधन से 77 हजार करोड़ तो दूसरी ओर केंद्र की प्राप्तियों से 66 हजार करोड़ रुपए का अनुमान जताया गया है। वहीं पूंजीगत प्राप्ति से 29 हजार करोड़ रुपए का अनुमान जताया गया है। वहीं व्यय की बात करें तो 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए राजस्व व्यय के तौर पर खर्च होंगे, वहीं पूंजीगत व्यय के तौर पर 26,500 करोड़ रुपए और ऋण एवं अग्रिम के तौर पर 500 करोड़ रुपए व्यय का अनुमान खींचा गया है।

इस बार छत्तीसगढ़ के बजट में सामाजिक क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए कुल व्यय का 40% प्रावधान किया गया है, जबकि आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए 36% और प्रशासनिक व सामान्य सेवाओं के लिए 24% राशि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14,300 करोड़ रुपए का विशेष ग्रीन बजट का भी प्रावधान किया गया है।

बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में सरगुजा, बस्तर और अन्य पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को केंद्र में रखा गया है। बस्तर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे अत्यंत संवेदनशील इलाकों में दो 'एजुकेशन सिटी' स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। खेल और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहलों के लिए बजट में संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सके और क्षेत्र की सकारात्मक पहचान मजबूत हो। इसके साथ ही बस्तर फाइटर्स के 1500 नवीन पदों का सृजन किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज एवं मेडिकल सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में डॉक्टरों की विशेष भर्ती की जाएगी, ताकि दूरस्थ इलाकों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण उपचार अपने ही क्षेत्र में मिल सके। सिंचाई क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए इंद्रावती नदी पर लगभग 2024 करोड़ रुपये की लागत से बैराज निर्माण की योजना घोषित की गई है। इससे बस्तर क्षेत्र में लगभग 32 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का अनुमान है।

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1 हजार पदों पर भर्ती होगी। छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 प्रमुख मिशन पर काम करेगी। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कृष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट का 70 प्रतिशत विभागों को : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट में 70 प्रतिशत हिस्सा विभागों को आवंटित किया है। यहां पर सरकार की प्राथमिकता सामने आती है. इसमें सबसे ज्यादा 13 प्रतिशत याने 22,360 करोड़ रुपए स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया है। वहीं 9.6 प्रतिशत याने 16,560 करोड़ रुपए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित किया गया है। इसके बाद कृषि (7.9 प्रतिशत), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (7.5 प्रतिशत), महिला एवं बाल विकास विभाग (6.4 प्रतिशत), लोक निर्माण विभाग (5.5 प्रतिशत), ऊर्जा के लिए (5.2 प्रतिशत), लोक स्वास्थ्य (5 प्रतिशत), गृह विभाग के लिए (4.9 प्रतिशत) और लोक स्वास्थ्य यात्रिकी के लिए (3.5 प्रतिशत) आवंटित किया गया है। **(शेष पेज-2 पर)**

'ज्ञान-गति' के बाद अब 'संकल्प'

साय सरकार ने तीसरे बजट का थीम 'संकल्प' रखा गया है। पहले व दूसरे बजट का थीम 'ज्ञान' व 'गति' था।

समावेशी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : चौधरी

विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश करने के बाद आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस बार संकल्प लेकर समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास पर फोकस किया है। इस बार का बजट छत्तीसगढ़ के विकास को और तेज गति प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो, भविष्य के अनुरूप कार्यबल तैयार हो, आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हो व प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल से उन्नत किया जा सके। पिछले बजट में हमने ज्ञान यानी (गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी) तथा गति यानी (गुड गवर्नेंस, एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नालाजी व इंडस्ट्रीयल ग्रोथ) पर फोकस किया था। इस साल बजट का थीम 'संकल्प' है। एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी भी होता है। उसका बेहतर उपयोग करना होता है।

प्रमुख विभागों के लिए बजट प्रावधान

- **स्कूल शिक्षा विभाग :** 22360 करोड़।
- **पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग :** 16560 करोड़।
- **कृषि विभाग :** 13507 करोड़।
- **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग :** 12820 करोड़।
- **महिला एवं बाल विकास विभाग:** 11000 करोड़।
- **लोक निर्माण विभाग:** 9451 करोड़।
- **ऊर्जा विभाग:** 9015 करोड़।
- **गृह विभाग :** 8380 करोड़।
- **लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग :** 8050 करोड़।
- **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग:** 3890 करोड़।

बजट में प्रमुख घोषणाएं

- रायपुर में 200 बिस्तरों का नया अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत होंगी।
- प्रदेश के 5 प्रमुख एयरपोर्ट पर शोरूम खोले जाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।
- सयानगुड़ी योजना का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा, इसके लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- रायपुर में ओबीसी छात्राओं के लिए 200 सीट क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा, जिससे उच्च शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
- भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान, ताकि उनकी आय और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने पर जोर रहेगा।
- कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
- रायपुर के कालीबाड़ी में 200 बिस्तरों वाला मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल निर्माण का प्रावधान किया गया है।
- 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य ग्राम सभा के माध्यम से कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय और क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे ग्रामीण सड़कों का विस्तार और कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
- मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट, जिससे राज्य में सड़क नेटवर्क को और बेहतर बनाया जाएगा।
- 5 नई नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं मिलेंगी।
- मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना लागू होगी, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- नवा रायपुर-राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ रुपए, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
- उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए किया गया, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू की जाएगी, जिससे महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- बस्तर और सरगुजा में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा, जैसे राइस मिल, पोल्ट्री फार्म और एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश प्रावधान।
- रानी दुर्गावती योजना शुरू होगी, जिसमें बच्चियों के 18 वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान, साथ ही 1000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।
- अभ्यारण्यों और वन्यजीव संरक्षण के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) खरीद पर सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जाएगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिलेगा।
- नवा रायपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।
- रायपुर में बनेगा पहला होमियोपैथी कॉलेज
- क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रावधान, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- अचल संपत्ति क्रय पर महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट।
- मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन, स्टार्ट अप एवं निपुण मिशन के लिए 100-100 करोड़ की घोषणा।
- बस्तर और सरगुजा विकास विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर में बनेगा होम्योपैथी कॉलेज।
- आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनेंगे।
- जशपुर, मैनपॉट और कोतेबेरा में पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
- राजधानी रायपुर में खाद लैब का निर्माण राज्य सरकार की तरफसे होगा।
- कांकेर, कोरबा, महासमुंद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज।
- मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान।
- 10 करोड़ रुपए से मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा।
- 206 गांव को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।

प्रदेश के विकास को नई गति देगा बजट : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे राज्य के बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवीन विधानसभा भवन में प्रस्तुत होने जा रहा हमारी सरकार का यह तीसरा बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विज़न को नई मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का यह बजट समावेशी विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट प्रदेश के 'सुशासन से समृद्धि' मॉडल को मजबूत आधार प्रदान करेगा और विकास की गति को और तेज करेगा। यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव संसाधन विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है और यह बजट उस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

यह संकल्प का नहीं, भ्रष्टाचार का बजट: नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किए बजट पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि यह बजट 'गति' का नहीं, बल्कि 'दुर्गति' का बजट है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प का नहीं, भ्रष्टाचार का बजट है। नई-नई योजनाएं भ्रष्टाचार करने के लिए लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शब्दों का मायाजाल बुना गया है। इस बजट में प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। नौकरी के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया गया है। जो हड़ताल कर रहे हैं, उनकी छोटी-छोटी मांगें हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही है।

बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं को कुछ नहीं मिला: पूर्व सीएम बघेल

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 'संकल्प' थीम पर आधारित 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट को लेकर विपक्षी दलों के नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर ने कहा कि यह अज्ञान और दुर्गति विनाश का बजट है। भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। दो घंटे सिर्फशब्दों का जाल बुना गया। मैं भी पांच साल बजट पेश किया हूं। एक-एक सड़क, चौक-चौराहों के नाम गिनाए जा रहे थे। धान खरीदी के नाम पर धोखा हुआ है। किसान का रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन खरीदी कम हुई है। बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल खेला गया है। मंत्रियों के बोलने के लिए कुछ नहीं है। मान्य परंपरा के विपरीत जा रहे हैं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय की घोषणाओं को बार-बार पढ़ा जा रहा है। रेलवे ट्रैक सिर्फयहां के खनिज को लूटने के लिए है। कोई स्टॉपेज नहीं होगा। यह सरकार का तीसरा बजट है, लेकिन मोदी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि आज क्या एक लाख बीस हजार में घर बन सकता है? जिसने बनाया है, वह साहूकार के कर्ज में लद गया है।

युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी तानाशाही : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एआई शिखर सम्मेलन के दौरान यहां भारतमंडपम में विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को तानाशाही करार देते हुए मंगलवार को कहा कि पार्टी युवा निडर साथियों के साथ मजबूती से खड़ी है। श्री गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा ÷शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने 'समझौतावादी प्रधानमंत्री' के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है। अमेरिका के साथ हुए व्यापार संज्ञौते में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और युवा संगठन के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है।

लोकसभा अध्यक्ष ने 64 पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाए, हर ग्रुप में एक लीडर समेत 11 सांसद

फ्रांस में थरूर, जापान में अखिलेश यादव नेतृत्व करेंगे

नई दिल्ली (ए)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को 64 देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स का गठन किया है। इन ग्रुप्स का मकसद दूसरे देशों के साथ संसदीय कूटनीति को मजबूत करना और वैश्विक मंच पर भारत की संसद की एकजुट लोकतांत्रिक आवाज पेश करना है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क पर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी ने भारत और अन्य देशों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए पीएफजी बनाने का प्रस्ताव दिया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ने इसका गठन किया है। 64 ग्रुप्स में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 704 सांसद हैं। हर ग्रुप में एक लीडर और 10 सदस्य हैं। इनमें भाजपा के सबसे ज्यादा 30 ग्रुप लीडर हैं। कांग्रेस के 10, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तृणमूल कांग्रेस के 3-3 सांसद ग्रुप लीडर बनाए गए हैं।

पश्चिम बंगाल एसआईआर में ओड़िशा-झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद इनका खर्च चुनाव आयोग उठाए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए झारखंड-ओडिशा के सिविल जजों की मदद ले सकता है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह 28 फरवरी को बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पोल पैनल सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। इससे पहले 20 फरवरी को, पश्चिम बंगाल सरकार और ईसी के बीच चल रही खींचतान से निराश होकर कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस में पोल पैनल की मदद के लिए मौजूदा और पूर्व जिला जजों को तैनात करने का निर्देश जारी किया था।

केरल का नाम अब केरलम कैबिनेट की मंजूरी

सेवातीर्थ में पहली मीटिंग, रेल-मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,236 करोड़ मंजूर

नई दिल्ली (ए)। पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में तीन रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं।

बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कैबिनेट ने तीन नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया-चांडिल और पुनारख-किऊल के बीच तीसरी-चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी है। साथ ही श्रीनगर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2बी का एक्सटेंशन होगा।

आंकड़ों में बजट

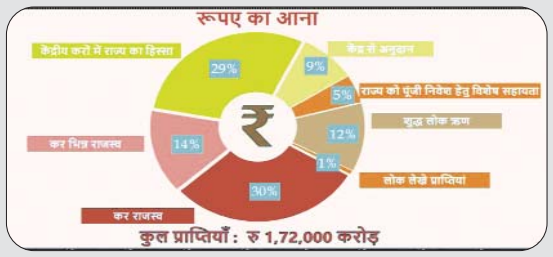

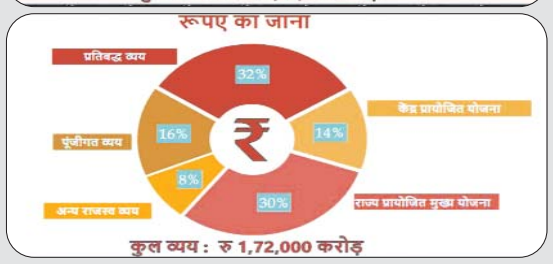

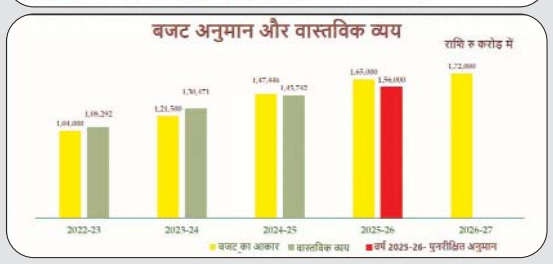

प्राप्तियाँ 2026-27

राशि रु करोड़ में

क्र.	मद	2026-27 (बजट अनुमान)
1	राजस्व प्राप्ति	1,43,000
1.1	राज्य का स्वयं का कुल राजस्व	77,000
	a. कर राजस्व	52,000
	b. कर भिन्न राजस्व	25,000
1.2	केंद्र से प्राप्तियाँ	66,000
	a. केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	51,000
	b. केंद्र से सहायता अनुदान	15,000
2	पूंजीगत प्राप्ति	29,000
	a. शुद्ध लोक ऋण	27,900
	b. उधार एवं अग्रिम की वसूली	100
	c. लोक लेखे प्राप्तियाँ	1,000
3	कुल प्राप्तियाँ	1,72,000

व्यय 2026-27

राशि रु करोड़ में

क्र.	मद	बजट अनुमान 2025-26	बजट अनुमान 2026-27
1	राजस्व व्यय	1,38,196	1,45,000
2	पूंजीगत व्यय	26,341	26,500
3	ऋण एवं अग्रिम	463	500
4	कुल व्यय	1,65,000	1,72,000

क्र.	मद	2026-27 (बजट अनुमान)
1	प्रतिबद्ध व्यय	55,000
1.1	वेतन	35,000
1.2	ब्याज	11,000
1.3	पेंशन	9,000
2	केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)	24,000
2.1	केंद्रीय योजनाओं को केन्द्रांश राशि	15,000
2.2	केंद्रीय योजनाओं को राज्यांश राशि	9,000
3	राज्य प्रायोजित मुख्य योजनायें	52,000
4	अन्य राजस्व व्यय	14,000
5	कुल राजस्व व्यय	1,45,000

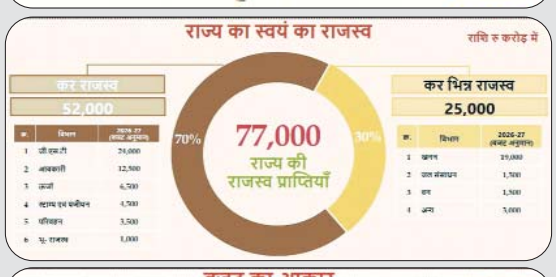

बजट में 10 नई योजनाएं का ऐलान

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। बजट में इस बार 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। ये योजनाएं विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना

रायपुर। बजट में मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता आदि का सुधार लाया जा सके।

मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना

द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तीव्र गति वाली 2 या 4 लेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना

स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा

राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सीजी एसीई योजना

प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता के लिए सीजी एसीई (छत्तीसगढ़ एसिस्टेंस फॉर कॉम्पीटेटिव एक्जाम) योजना के अंतर्गत 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तीन घटक है- उड़ान, शिखर व मंजिल के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रवेश तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य शासन की ओर से आर्थिक सहायता की जाएगी। उड़ानः नीट/जेईई/क्लैट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।शिखरः यूपीएससी/सीजीपीएससी के लिए। मंजिलः रेलवे/बैंकिंग/एसएससी के लिए।

सीजी वायु योजना

सीजी वायु (छत्तीसगढ़ वायबिलीटी एसिस्टेंस फार यात्री उड़ान) के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना है।

रानी दुर्गावती योजना

परिवार में बालिका के जन्म पश्चात, बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना

आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के लिए रेंटल आवासीय सुविधा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

लखपति दीदी भ्रमण योजना

सरकार ने इस साल को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में प्रदेश की लखपति दीदियों को, सफल महिला उद्यमियों की कार्य प्रणाली तथा उनके सफल व्यवसाय माडल का अध्ययन करने के लिए देश के अंदर आर्थिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए लखपति दीदी भ्रमण योजना में 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के 5 शक्तिपीठ- कुदरगढ़, रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़ और दंतेवाड़ा स्थिति आस्था केंद्रों के दर्शन के लिए आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना

शासकीय स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राज्य के अंदर प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के भ्रमण के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध परम्पराओं एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाजों का ज्ञान करवाने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पांच मुख्यमंत्री मिशन से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार व नई रफ्तार मिलेगी

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए ब जट में 5 मुख्यमंत्री मिशन का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से चिन्हांकित क्षेत्रों में मिशन मोड में कार्य किया जाएगा।

1. मुख्यमंत्री एआई मिशन

सीएम एआई मिशन का उद्देश्य राज्य को उभरती हुई प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाना है, जिसके तहत युवाओं के कौशल विकास, एआई आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा तता प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

2. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन

यह मिशन जमीनी स्तर के खेल प्रतिभाओं की पहचान और संवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। मिशन के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित करना और

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। महिला खिलाड़ियों की भागीदारी को जोर दिया जाएगा।

3. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन

यह मिशन राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों और थीम आधारित सर्किटों की पहचान करना तथा विकास पर केंद्रित है। इसमें मेले, उत्सव, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, होमस्टे, टूर गाइड का कौशल विकास और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना शामिल है।

4. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन

यह मिशन राज्य में आधारभूत अधोसंरचना विकास के लिए एक मौजूदा तथा आवश्यक महत्वपूर्ण अधोसंरचना/परियोजनाओं का गैप एनालिसिस करते हुए समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करेगा।

5. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन

स्टाअप मिशन का उद्देश्य राज्य के युवाओं को जाब सीकर से जाब क्रिएटर बनाना है। मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप्स को तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा।

वहीं निपुण (न्यू एज इंडस्ट्रीयल प्रीपेयर्डनेस फर अपस्कीलिंग न्यू जनरेशन यूथ) मिशन युवाओं को उद्योग संगत कौशल प्रदान कर युवाओं को नई तकनीक आधारित उद्योगों में सृजित हो रहे नवीन अवसरों के लिए तैयार करेगा। अगले पांच सालों तक इन मिशनों के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 100-100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा।

आंकड़ों में बजट

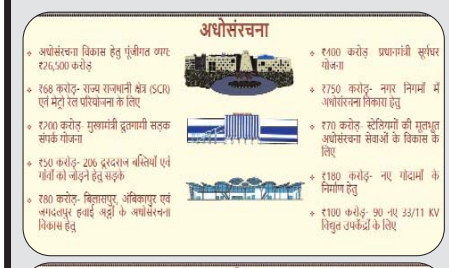

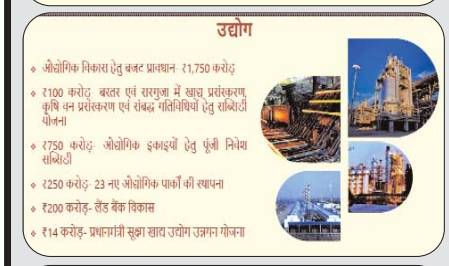

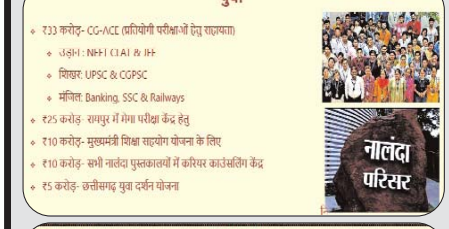

1,500 नए बस्तर फाइटर्स पदों पर होगी भर्ती, 15 नए पुलिस थाना खुलेंगे

समवेत शिखर संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बार संकल्प थीम पर वित्तीय वर्ष 2026 का बजट पेश किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बस्तर में 1,500 नए बस्तर फाइटर्स पदों का सृजन किया जाएगा।यह पहल बस्तर में सुरक्षा के साथ-साथ विश्वास और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। स्थानीय युवाओं को सुरक्षा बलों में शामिल कर क्षेत्र में नक्सल प्रभाव को कम करने और जनता तथा पुलिस के बीच भरोसे को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साइबर अपराध रोकने के लिए 5 नए थाना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि बस्तर फाइटर्स योजना से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं की भागीदारी से सुरक्षा तंत्र भी और अधिक प्रभावी बनेगा। यह पहल बस्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आने वाले समय में क्षेत्र के समग्र विकास के लिए और भी योजनाएं शुरू की जाएंगी।

बजट की खास बातें

- 1,500 नए बस्तर फाइटर्स पदों का सृजन किया जाएगा।
- 15 नए पुलिस थाना खुलेंगे।
- 5 नए साइबर थानों का प्रदेश में निर्माण होगा।
- महिला थानों की संख्या बढ़ेगी।
- तेलीबांधा रायपुर थाना का होगा नवीनीकरण।
- सीन ऑफक्राइम यूनिट की स्थापना के लिए 3 करोड़ का प्रावधान।

प्रथम पेज का शेष

बजट 2026-27 : विकसित छत्तीसगढ़ के लिए 'संकल्प'

किसानों से जुड़ी योजना पर सर्वाधिक व्यय : साय सरकार अपने तीसरे बजट में सर्वाधिक 10 हजार करोड़ रुपए कृषक उन्नति योजना पर खर्च करेगी, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता और कृषि विकास को गति मिलेगी। कृषि पंपों के लिए 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, वहीं भूमिहीन कृषि परिवारों के समर्थन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, एग्रो-फॉरेस्ट प्रोसेसिंग, राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में मदद मिलेगी।

बालिकाओं को 1.5 लाख : छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'रानी दुर्गावती योजना' शुरू की जाएगी, जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पात्र बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसक साथ ही 'मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना' लागू की जाएगी, वहीं उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 250 महतारी सदनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना : बजट में शासकीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैशलेस चिकित्सा योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उपचार के दौरान अस्पताल में नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% मिलेगी छूट : रायपुर। आज विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरी बार राज्य का बजट पेश किया। अपने बजट में उन्होंने देश की आधी आबादी नारी शक्ति को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीकरण पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% की छूट की घोषणा की है। इसे एक बड़ी घोषणा के रूप में माना जा रहा है। हालांकि यह नियम आगामी वर्ष से लागू होगा। वित्त मंत्री चौधरी ने घोषणा करते हुए बताया कि यह हमारे संकल्प पत्र के अनुसार है। महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में निरंतरता रखते हुए एवं हमारे संकल्प पत्र के अनुरूप आगामी वर्ष से महिलाओं के नाम से अचल संपत्ति क्रय पर भारित पंजीयन शुल्क में 50% की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

बजट में नई पहल

समवेत शिखर संवाददाता

रायपुर। इस साल प्रस्तुत की गई नई पहलें राज्य की उभरती हुई प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इन पहलों का उद्देश्य नई संभावनाओं की पहचान कर राज्य की समावेशी प्रगति एवं आर्थिक उन्नति की दिशा में निर्णायक कदम उठाना है।

1. अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी

अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ और जगरगुंडा को शिक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित करना है।

2. नए औद्योगिक पार्क

राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

3. लैंड बैंक विकास योजना

लैंड बैंक विकास योजना के लिए 200 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। इससे औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

4. बस्तर एवं सरगुजा में औद्योगिक विकास

बस्तर एवं सरगुजा में औद्योगिक विकास के लिए खाद्य, एग्रो फारेस्ट्री, कृषि एवं कृषि संबंधी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5. इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0

राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6. सिरपुर विकास योजना

सिरपुर विकास योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

जन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के लिए 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

न्यूज ब्रीफ

राज्यपाल से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने भेंट की

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां लोकभवन में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्र भूषण वर्मा ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर अंबिका चंद्रवंशी, श्री मुरली चंद्राकर, श्री जय प्रकाश वर्मा, श्री रवि वर्मा, श्री मिलिंद चंद्राकर, श्री रामगोपाल वर्मा उपस्थित थे।

कोयला घोटाला केस : आरोपी नारायण साहू गिरफ्तार

रायपुर। कोयला घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी नारायण साहू को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि, वो आरोपी सूर्यकांत तिवारी का करीबी सहयोगी रहा है। केस में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोयला लेवी की राशि के कलेक्शन और पैसों के ट्रांसफर का भी काम करता था। ईओडब्ल्यू के अनुसार, जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि, सूर्यकांत तिवारी की तरफसे नारायण साहू के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी गई थी। आरोपी पिछले करीब ढाई साल से फरार चल रहा था।एजेंसी की पूछताछ से लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पहले ही न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय की अनुमति से उसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

छत्तीसगढ़ में होली पर नहीं बिकेगी शराब, दुकानें बंद रहेंगी, सरकार ने जारी किया आदेश, पहले हटाया गया था ड्राई डे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर स्थिति एक बार फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने होली पर शराब बिक्री की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। आबकारी विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दैनिक भास्कर डिजिटल ने होली पर शराब बिक्री पर रोक की खबर सुबह ही बता दी थी। नई आबकारी नीति में पहले तय 7 ड्राई डे में से तीन दिन होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) को हटाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद माना जा रहा था कि इन दिनों शराब दुकानें खुली रहेंगी। अब सरकार ने रुख बदलते हुए होली पर शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यानी होली के दिन राज्यभर में शराब दुकानें बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि सामाजिक और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले जैसा ही लागू रहेगी।

रायपुर कलेक्ट्रेट के पास खड़ी कार में लगी आग

रायपुर। राजधानी रायपुर में आज कलेक्ट्रेट के पास खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार से धुआं और लपटें उठीं, आसपास मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आग किस वजह से लगी और कार किसकी थी, इसकी जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, कार सड़क किनारे खड़ी थी तभी अचानक आग भड़क उठी। घटना घड़ी चौक की है। रायपुर में कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप पर भी आगजनी की घटना सामने आई थी। उरला थाना क्षेत्र में सिगरेट पीने से मना करने पर नाराज युवक ने नोजल पाइप में लाइटर से आग लगा दी थी। आग नोजल पाइप के साथ पेट्रोल भरवा रहे युवक की बाइक की टंकी तक पहुंच गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था।

सनाढ्य ब्राह्मण सभा की बैठक

रायपुर। सनाढ्य ब्राह्मण सभा रायपुर की सामाजिक बैठक शहर के मारुति लाइफस्टाइल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दुबे ने की। इस दौरान सामाजिक एकता, संगठन की मजबूती और हिंदू संस्कारों के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई। समाज के सदस्यों को सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

निवेश, उद्योग और रोजगार आधारित आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है बजट : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री देवांगन

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत राज्य के वर्ष 2026-27 के बजट संकल्प 2026-27 को छत्तीसगढ़ को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक, संतुलित एवं दूरदर्शी बजट बताया है। उन्होंने इस जनोन्मुखी एवं विकासपरक बजट के लिए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

श्री देवांगन ने कहा कि 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित प्रावधान वाला यह बजट राज्य की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करते हुए निवेश, औद्योगिक विस्तार और व्यापक रोजगार सृजन की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करता है। प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार पर विशेष बल दिया गया है, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 रोजगार केंद्रित है। विगत वर्ष लगभग 1,000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनके माध्यम से 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ तथा 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर निर्मित हुए। यह राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण एवं औद्योगिक विश्वास का सशक्त संकेत है। उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिनमें मटीया (कसडोल), बिरकोनी (महासमुंद), छाती (धमतरी), बनगांव-बी (पत्थलगांव) सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए लैंड बैंक तैयार करने हेतु 200 करोड़ रुपये तथा उद्योगों को अनुदान एवं प्रतिपूर्ति के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पूर्व की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले के कचना में 17 एकड़ क्षेत्र में प्रदेश की पहली चार मंजिला प्लग-एंड-प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। ग्राम तूता, नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेंशन सह एक्जिबिशन सेंटर के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये, भिलाई में व्यावसायिक परिसर हेतु 10 करोड़ रुपये, पटेवा (राजनांदगांव) में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 हेतु 10 करोड़ रुपये तथा नवा रायपुर अटल नगर एवं राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रदेश के औद्योगिक अधोसंरचना विकास को नई गति देगा। श्री देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद तथा जापान के ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संभावनाओं और वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि Ease of Doing Business के अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम एवं छत्तीसगढ़ जन विश्वास अधिनियम जैसे सुधारात्मक कदमों के माध्यम से शासन उद्योगों के लिए सुगम, पारदर्शी और प्रोत्साहनकारी वातावरण उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2024-25 में उद्योग विभाग का बजट 648 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 1,750 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि राज्य सरकार की उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

विकास, महिला सशक्तीकरण और समावेशी प्रगति का आधार है बजट: रमेश सिंह ठाकुर

1.72 लाख करोड़ के बजट को रायपुर भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया ऐतिहासिक व दूरगामी

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी, जिला रायपुर के जिलाध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर ने इसे राज्य के विकास की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया है। जिलाध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। हमारी भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य के समावेशी विकास को नई गति देगा तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस जनकल्याणकारी बजट का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसे प्रदेश की प्रगति का सशक्त आधार मानते हैं। उन्होंने बजट की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बालिकाओं को 1.50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई एवं विकास को गति देने के लिए मठनार एवं देउर गांव बैराज निर्माण हेतु 2024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की आय वृद्धि और कृषि सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अबूझमाड़ एवं जगरगुड़ा में एजुकेशन सिटी स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

बिना रोड मैप का दिशाहीन और निराशाजनक बजट : गंगवानी

आम आदमी की उम्मीदों और अपेक्षाओं के विपरीत बजट

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने बताया कि आज वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने सांय सरकार का तीसरा बजट पेश किया, इस बजट से छत्तीसगढ़ की आम जनता किसान युवा महिला और आदिवासी, कर्मचारी, व्यापारी और गरीब एक उम्मीद और आस लगाकर बैठे थे कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास होगा, सांय सरकार उनके जेब में सीधे पैसा डालने का काम करेगी. उन्हें उम्मीद थी कि सांय सरकार का यह बजट समृद्धि का बजट होगा, वित्तीय अनुशासन का बजट होगा, जनकल्याणकारी योजनाओं और छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट होगा परंतु यह बजट पूरी तरह जुमलेबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी का बजट है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने बताया कि ना इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया, ना 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की मोदी गारंटी को पूरा करने का कोई ईमानदार प्रयास दिखा. छत्तीसगढ़ की माताएं और बहनें इस बार उम्मीद और लगा कर बैठी थी कि 500 में सिलेंडर देने की मोदी गारंटी को पूरा करने की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी करेंगे परंतु वह भी पूरी तरह निराश हुई. मोदी गारंटी में 100 दिन में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करने वाली सांय सरकार ने फिर छत्तीसगढ़ के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को ठगा. वित्त मंत्री का यह बजट छग के आम आदमी उम्मीद अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के पूरी तरह विपरीत निकला, हर वर्ग निराशा और हताश है सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे है। छत्तीसगढ़ में अब अपराध चरम पर हैं रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार और प्रतिदिन तीन हत्याएं हो रही, शायद सरकार को ढाई साल के बाद 15 ने पुलिस थानों और पांच साइबर थानों की याद आई. एक्साइज के रेवेन्यू कलेक्शन में 10000 करोड़ रुपए की वृद्धि इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सांय सरकार की प्राथमिकताओं में आम आदमी का हित न होकर शराब से मिलने वाली काली कमाई है।

राज्य बजट से सामाजिक कार्यों का विस्तार होगाः अजय काले

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल की विभिन्न समितियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के तीसरे बजट को राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से ले जाने वाला और सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला बजट बताया। अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के वित्तमंत्री ओपी चौधरी की ओर से प्रस्तुत तीसरे बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, उससे सामाजिक कार्यों का विस्तार होगा। काले ने कहा कि सियान गुड़ी जैसे वरिष्ठ सदस्यों की कल्याण योजना के लिए वार्षिक बजट में सम्मानजनक राशि का प्रावधान किया गया है, जो संवेदनशील नीति का द्योतक है। युवाओं के शिक्षण विस्तार के लिए महाविद्यालय स्थापना, भवन निर्माण, नालंदा वाचनालय, युवाओं के कैरियर गाइडेंस के लिए व बच्चियों के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 15 हजार रुपये राशि और स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट प्रावधान प्रशंसनीय है।

'ज्ञान' और 'गति' के 'संकल्प' से विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता ऐतिहासिक बजट: शर्मा

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 को प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में दूरदर्शी, संतुलित और विकासोन्मुख बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि 'ज्ञान' और 'गति' के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की सशक्त कार्ययोजना है। उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16 हजार 5 करोड़ रुपये से अधिक और गृह विभाग के लिए 8,380 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। शिक्षा, कौशल विकास, अधोसंरचना, निवेश, अंत्योदय, आजीविका और कुशल मानव संसाधन निर्माण पर केंद्रित यह बजट सर्वस्पर्शी विकास का प्रतीक है। आवासहीनों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4-4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य की संवेदनशील और प्रतिबद्ध सरकार का प्रमाण है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद के प्रभाव से उबरते बस्तर में अब विकास की नई धारा बहेगी। 1500 बस्तर फाइटरों की भर्ती स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

अशोक कुसरे के नेत्रों से दो नेत्रहीन देख सकेंगे दुनिया

महाराष्ट्र मंडल के देहदान-नेत्रदान महादान प्रभारी विक्रम हिशीकर का एक और सेवाभावी प्रयास

समवेत शिखर न्यूज

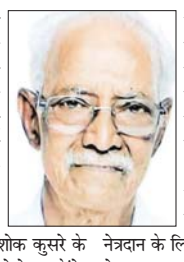

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के 'देहदान- नेत्रदान महादान अभियान' के प्रभारी विक्रम हिशीकर के प्रेरक प्रयास से मंडल के आजीवन सभासद तात्यापारा स्थित कुसरे बाड़ा निवासी अशोक कुसरे के निधन के उपरांत उनके बेटा-बहू ने उनका नेत्रदान कराया। इस महादान पहल से अब अशोक कुसरे के नेत्रों से दो नेत्रहीन इस दुनिया को देख सकेंगे।

अशोक की पुत्रवधू, महाराष्ट्र मंडल की सभासद और संत ज्ञानेश्वर स्कूल की शिक्षिका अस्मिता कुसरे ने बताया कि सोमवार को दोपहर दो बजे ससुर के निधन पर जब पूरा परिवार शोक संतप्त था, तो इसी बीच विक्रम ने सुझाव दिया कि पिता की आंखें यदि तत्काल निर्णय लेकर दान की जाएं, तो इससे दो नेत्रहीन बच्चे दुनिया देख सकेंगे। इस सुझाव पर कुसरे परिवार सहमत होकर नेत्रदान करने के लिए तैयार हुआ। इस तरह एमजीएम नेत्र संस्थान रायपुर में अशोक बाला साहेब कुसरे का नेत्रदान कराया गया। मंडल के 'देहदान-नेत्रदान महादान अभियान' के प्रभारी विक्रम ने सभी सदस्यों और जन सामान्य से अपील की है कि ऐसे कार्यों से प्रेरित होकर न सिर्फ लोगों को देहदान व नेत्रदान के लिए प्रेरित करें, बल्कि स?वयं भी नेत्रदान का फार्म भरकर दूसरों के लिए मिसाल बनें। बताते चलें कि महाराष्ट्र मंडल के अध?यक्ष अजय मधुकर काले 41 साल देहदान और नेत्रदान का फार्म भरकर पहले ही इसके लिए संकल्पबद्ध हैं।

रायपुर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन काले डस्ट और खराब एयर क्वालिटी को लेकर नारेबाजी

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। रायपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण और काले डस्ट की समस्या को लेकर कांग्रेस ने आज पर्यावरण कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हुए इस विरोध में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पर्यावरण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि, शहर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि, रायपुर में सड़कों पर उड़ने वाली काली धूल, निर्माण कार्यों से उठता मलबा, ट्रांसपोर्ट नगर और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं और बढ़ते वाहनों के दबाव के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ा रहा है। शहर के कई इलाकों में सुबह-शाम धूल की परत साफ नजर आती है। लोगों को आंखों में जलन, खांसी, एलर्जी और सांस लेने में तकलीफजैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक, अस्थमा और श्वसन संबंधी मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि, पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों का स्तर कई बार मानक सीमा के आसपास या उससे ऊपर पहुंच जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कांग्रेस का आरोप है कि इन मुद्दों पर पर्यावरण विभाग और नगर निगम समन्वित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पार्षद और विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल सहित कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने मांग की है कि, शहर के लिए ठोस प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना बनाई जाए, नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में हलचल रही, हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा।

कलेक्टर ने पशु चिकित्सा कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज पशु चिकित्सा कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आधार आधारित उपस्थिति की जांच की तथा उपस्थिति पंजी एवं डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से आधार आधारित उपस्थिति दर्ज करें तथा समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कार्यालय के स्टोर रूम एवं अन्य कक्षों का भी निरीक्षण किया एवं वहां उपलब्ध दवाइयों, उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की स्थिति की जानकारी ली तथा स्टॉक रजिस्टर का परीक्षण किया।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पशु चिकित्सा सेवाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कार्यालय की कार्यप्रणाली सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन, संयुक्त संचालक पशु स्वास्थ्य सेवाएं डॉ शंकर लाल उइके सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला चिकित्सालय स्थित हेल्दी लाइफ स्टाइल क्लीनिक का निरीक्षण

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिला चिकित्सालय परिसर स्थित हेल्दी लाइफ स्टाइल क्लीनिक का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्लीनिक में स्काई ग्रुप के ष्ह्यह्न द्धह्वठ्ठस्र के तहत निशुल्क भोजन वितरण की सराहना की। क्लीनिक के संचालक श्री अग्रवाल ने बताया कि हर मंगलवार को स्काई समूह एवं रोटरी क्लब ऑफरायपुर द्वारा संयुक्त रूप से करीबन 400 लोगों को निशुल्क भोजन कराया जाता है। क्लीनिक में योग, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, डाइटेशन एवं मेडिटेशन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर डॉ सिंह ने वहां उपस्थित चिकित्सकों एवं स्टाफसे चर्चा कर सेवाओं की नियमितता, लाभार्थियों की संख्या एवं व्यवस्थाओं के संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि जीवनशैली संबंधी रोगों की रोकथाम एवं उपचार के लिए इस क्लीनिक को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ली डाक सेवकों की समीक्षा बैठक

रायपुर। लेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने डाक सेवकों की ली समीक्षा बैठक। कलेक्टर डॉ. सिंह ने डाक सेवकों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप सभी रोजाना अपने डाक घरों में 0 से 05 वर्ष की आयु के बच्चों का आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य 25 से अधिक रखें ताकि सभी बच्चों का आधार कार्ड जल्द से जल्द बन सके एवं आप सभी अपनी डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजें। डाक सेवक यह सुनिश्चित करें कि शासन की इस महत्वकांशी योजना का लाभ हर नागरिक को मिले। कलेक्टर ने परिजनों से आग्रह किया कि जिनके बच्चों की उम्र 0 से 05 वर्ष की है वे 31 मार्च से पूर्व निःशुल्क रूप से अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवालें, मार्च 2026 के बाद यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड बनाने पर शुल्क लिया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

टीम प्रहरी द्वारा डूंडा में करीब 50 करोड़ मूल्य की जमीन को कराया गया मुक्त

329 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग सहित 675 प्रमुख स्थानों पर की गई सख्त कार्रवाई

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर। टीम प्रहरी द्वारा रोजाना राजधानी की प्रमुख सड़कों पर अतिक्रमण हटाने, अवैध प्लॉटिंग एवं यातायात व्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई की जाती है। रायपुर शहर में अब तक 329 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग की शिकायतों पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गयी है। अब तक शहर के 675 प्रमुख स्थानों पर कार्यवाही की जा चुकी है एवं नियमों का उल्लघन करने वालों पर 65 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।

टीम प्रहरी द्वारा मालवीय रोड तेलीबांधा रोड, संतोषी नगर चौक, पचपेड़ी नाका चौक, गौरव पथ, एन.आई.टी. कॉलेज के सामने, टाटीबंध, समता कालोनी, लालपुर चौक, अम्लीडीह मार्ग, तेलीबांधा चौक से मरीन ड्राइव चौक तक, जेल रोड फाफाडीह चौक, मौदहापारा, घड़ी चौक, जयस्तंभ चौक, विधानसभा एवं अवंति विहार मुख्य मार्ग सहित अन्य स्थानों पर जाकर अतिक्रमण हटाने एवं रायपुर में अवैध निर्माण पर रोकथाम की कार्यवाही करते हैं। हाल ही में सेक्टर-10 डूंडा क्षेत्र में आर.डी.ए. की 26 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया, जिसका अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रूपये है। यह भूमि पुनः रायपुर विकास प्राधिकरण को वापस सौंप दी गयी है। उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा 25 जनवरी 2025 को 'टीम प्रहरी' की शुरूआत की गई थी। जिसका उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण को हटाना है। इस टीम में रायपुर नगर पालिक निगम के 30 पुरुष एवं 20 महिला सदस्य, जिला प्रशासन के 05 अधिकारी, पुलिस विभाग के 15 जवान और यातायात विभाग के 10 अधिकारी शामिल हैं।

शिखर बने उतुंग, शिखर अपने प्रताप से।
डरे कभी वह नहीं, किसी के उग्र शाप से।।

संपादकीय

भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते की राह

भारत के हित में यही है कि उसके उत्पादों की खपत विश्व के अधिक से अधिक देशों में हो। भारत को अपने उत्पादों के लिए अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों को अनुकूल बाजार के रूप में इसलिए भी खोजना चाहिए, क्योंकि इससे ही वह ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के दबदबे को खत्म कर सकता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रंप की टैरिफ नीति को अवैधानिक करार देने के उपरांत भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार वार्ता टलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह यह कहा कि फिलहाल टैरिफ में बदलाव को लेकर कुछ कहना कठिन है, उससे इसे लेकर सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका से व्यापार समझौता कब होगा? जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने 25 प्रतिशत टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने एवं रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को खत्म करने की घोषणा की थी और उसके बाद दोनों देशों की ओर से व्यापार समझौते को लेकर संयुक्त बयान जारी किया गया था तो माना जा रहा था कि मार्च में यह समझौता हो जाएगा। फिर मार्च के स्थान पर अप्रैल में समझौता होने की संभावना व्यक्त की गई, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिढ़े ट्रंप की ओर से सभी देशों पर पहले 10 और फिर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद व्यापार समझौते को लेकर संशय पैदा हो गया है। फिलहाल न तो यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता कब होगा और न ही यह कि इस समझौते की टैरिफ दरें क्या होंगी? यह ठीक है कि वाणिज्य मंत्रालय बदले हालात की समीक्षा कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ ट्रंप प्रशासन के रवैये पर निर्भर करेगा, जिसके स्थिर रहने का ठिकाना नहीं। इन स्थितियों में भारत के लिए उचित यही होगा कि वह अन्य देशों से व्यापार समझौते संबंधी वार्ताओं को गति प्रदान करे। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ आदि के साथ जो व्यापार समझौते हो चुके हैं, उन्हें अंतिम रूप देने का काम यथाशीघ्र किया जाए। यह सही है कि भारत समेत अन्य देशों के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है और उसके साथ व्यापार समझौता भारतीय कारोबारियों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के हित में है, लेकिन भारत को अपने उत्पादों एवं सेवाओं की खपत के लिए अन्य विकल्प तलाशने का काम प्राथमिकता के आधार पर करते रहना चाहिए। इसमें इसलिए ढील देना उचित नहीं होगा कि अंततः अमेरिका से व्यापार समझौता होना ही है। भारत के हित में यही है कि उसके उत्पादों की खपत विश्व के अधिक से अधिक देशों में हो। भारत को अपने उत्पादों के लिए अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों को अनुकूल बाजार के रूप में इसलिए भी खोजना चाहिए, क्योंकि इससे ही वह ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के दबदबे को खत्म कर सकता है और उन देशों की आकांक्षा भी पूरी कर सकता है, जो भारत को चाइना प्लस वन रणनीति के तहत एक प्रमुख देश के रूप में देख रहे हैं। निःसंदेह यह सब तब संभव होगा, जब भारतीय कारोबारी अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता विश्वस्तरीय बनाएंगे।

पर्यावरण सुधारने से बचेगी चारोंधाम की पवित्रता और अस्तित्व

■ योगेंद्र योगी

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने कहा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 47 प्रमुख मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव में जैन, सिख और बौद्ध समुदायों को छूट दी जाएगी। समिति की तरफ से कहा गया है कि मामला किसी विशेष धर्म का नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक अनुशासन का है, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है, उसके लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के द्वार खुले हैं। उसके पवित्र स्थलों की मूल प्रकृति को बनाए रखने के लिए सख्त कदम जरूरी है। प्रस्ताव का यह प्रतिबंध केवल मुस्लिम और ईसाई समुदाय पर लागू होगा। जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को छूट देने के पीछे तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 25 के तहत इन्हें हिन्दू परंपरा के अंतर्गत माना गया है। इस प्रस्ताव को जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

सवाल यही है कि सिर्फ मुस्लिम और ईसाइयों को बाहर रखने से ही क्या मंदिरों की पवित्रता बची रहेगी। क्या यही असली चुनौती है। चारो धाम पर जो पर्यावरण का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, उससे पवित्रता खतरे में नहीं है। हिन्दुओ के चार वेद एवं 18 पुराणों में से एक प्रमुख स्कंद पुराण में की गई भविष्यवाणी के अनुसार कलियुग के हजारों वर्षों बाद और इसके अंत से पूर्व केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल अदृश्य हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। इस भविष्यवाणी का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है की कोई शक्ति जाकर इन मंदिरों को तोड़ देगी या नष्ट कर देगी। बल्कि स्कंद पुराण के अनुसार कलियुग के अंत में जब धर्म का पतन अपने चरम पर होगा, तब यह दिव्यस्थल अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समेट लेंगे और अदृश्य या भक्तों की पहुंच से दूर हो जाएंगे।

उपरोक्त भविष्यवाणी यह चेतावनी है कि कलियुग में हमें धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि कलयुग में पवित्र स्थल और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। साल 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा को भी कुछ लोग इस भविष्यवाणी की झलक मानते हैं। 15 जून 2025 को रुद्र प्रयाग में एक हेलिकाप्टर दुर्घटना ग्रस्त हो गया है। जिसमें सवार सभी तीर्थ यात्रियों के मृत्यु हो गई। कुछ लोग इसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रतीकात्मक मानते हैं कि अगर हम पर्यावरण का नाश करेंगे तो धर्म हमसे दूर होता चला जाएगा। मौजूदा दौर में प्राकृतिक आपदाएं या सामाजिक पतन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ये इस बात का संकेत है कि इस पूरे क्षेत्र में दशकों

से चले आ रहे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने हालात बिगाड़ दिए हैं। इसके बावजूद जितनी गंभीरता से पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

साल 2013 में केदारनाथ में भयंकर विनाशकारी आपदा आई थी। केदारनाथ आपदा में 4400 से अधिक लोग मारे गए। 7 फरवरी 2022 को धौली और ऋषि गंगा का ऐसा सैलाब आया, जिसमें सैकड़ों जिंदगियां दफ्न हो गई थी। इस आपदा ने न सिर्फ 204 लोगों की जान ले ली, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले सभी बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया। आपदा में करीब 1,625 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। वर्ष 2025 में 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए, जो पिछले साल अर्थात 2024 की तुलना में 4 लाख 35 हजार अधिक है। केदारनाथ यात्रा के दौरान डेढ़ से 2 टन कचरा रोजाना उत्पन्न होता है। वर्ष 2025 की यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड 17.68 लाख भक्तों ने लगभग कुल 2300 टन से अधिक कचरा फैलाया है, जिसमें 100 टन प्लास्टिक शामिल है। हिमालयी क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर बैन होने के कारण, इस मलबे को खच्चरों द्वारा सोनप्रयाग नीचे लाने में ?25 करोड़ से अधिक की लागत आ रही है। यह कचरा पिछले साल की तुलना में 325 टन अधिक है। जिसमें 2200 टन ठोस कचरा और लगभग 100 टन प्लास्टिक शामिल है। हर तीर्थयात्री ने औसतन 1.5 किलो से ज्यादा कचरा छोड़ा। भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यह कचरा 23 अक्टूबर 2025 को कपाट बंद होने के बाद सफाई अभियान के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच मिला।

जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, अल्मोड़ा और उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक चारधाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ ग्रीष्मकालीन के साथ ही शीतकालीन गतिविधियों को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे में ग्लेशियरों के पीछे खिसकने की वजह से भूस्खलन हिमस्खलन चट्टानों के गिरने समेत खतरों को बढ़ा रहा है। यही नहीं, ग्लेशियर के पीछे हटने से हैकिंग ट्रेल्स और पर्वतारोहण मार्गों में भी बदलाव आ रहे हैं। लिहाजा, चारधाम में बढ़ रही भक्तों की भीड़ की वजह से पर्वतीय पर्यटन पर प्रभाव पड़ रहा है। मुख्य रूप से, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने की वजह से चारधाम यानी बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के समीप मौजूद ग्लेशियर न सिर्फ तेजी से पिघल रहे हैं बल्कि सालाना धामों के तापमान भी 0.02 से 0.05 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो रही है। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हजारों एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि राज्य तंत्र की विफलता के कारण ÷23 साल लग गए÷ और अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी शांत बने रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण और कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण/पेड़ों की कटाई पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को ÷मूकदर्शक÷ बने रहने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने, जांच के लिए समिति गठित करने और पारिस्थितिक नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए थे। उत्तराखंड में हज़ारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्ज़े के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कार्यकारी पद पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति इस लापरवाही के लिए जवाबदेह है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपको अवैध कब्ज़े का पता लगाने में 23 साल का समय लग गया। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार को पर्यावरण बचाने की कितनी चिंता है, इसके विपरीत धार्मिक भावनाओं को भुनाने के लिए पवित्रता बचाने की कवायद की जा रही है। उत्तराखंड में मानवीय गतिविधियों के विस्फोट से ये भयावह हालात पैदा हुए हैं। व्यवसायिक गतिविधियों के लालच ने उत्तराखंड को विनाश के कगार पर धकेला है। इंसानों द्वारा प्रकृति को दिए गए घावों से उत्तराखंड कराह रहा है। हालात ये हैं कि पर्यटन और धार्मिक आस्था के नाम पर उत्तराखंड पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है।

इस पेज में प्रकाशित लेख लेखक के उनके निजी विचार हैं।

प्रेरक प्रसंग

सबसे अच्छा दोस्त

एक बार की बात है, दो दोस्त एक साथ रेगिस्तान से गुजर रहा था। जाते जाते रस्ते में दोनों के बीच एक बात को लेकर बहस हुई। उस बात को लेकर एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरी दोस्त की गालो पे जोर से थप्पड़ मारा।जो मार खाया उसने बहुत ही गुस्सा किया, उसकी गालों पे चोट लगी थी। उसने बिना कुछ कहें रेत पर लिखा ÷आज मेरा सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा।÷फिर दोनों दोस्तों ने रेगिस्तान में चलना शुरु किया। तब तक चलते रहे जब तक दोनों को रेगिस्तान में पानी नहीं मिला। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को एक नदी दिखी, फिर दोनों ने नहाने का फैसला किया।दोनों दोस्त जाकर पानी में नहाने लगे। थोड़ी देर बाद जिसने थप्पड़ खाया वह पानी में फँस गया और डूबने लगा तब दुसरे दोस्त ने उसे बचा लिया। उसने नदी से बाहर आकर एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था उसने दूसरे दोस्त को पुछा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया तो बाद में तुमने रेत पे लिखा। और जब मैं तुम्हें पानी में डूबते हुए बचाया तो तुमने क्यों एक पत्थर पर लिखा?÷दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, ÷जब तुम हमें चोट पहुंचाए तब मैंने रेत पर लिखा था क्यूंकि अगर जोर से हवा आई तो लिखा मिट जायेगा। जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो तब हम पत्थर पर लिखे क्यूंकि पत्थर में लिखे को कोई भी हवा मिटा नहीं सकती। उसके बाद दोनों दोस्त बात करते करते अपने घर चले गए।

धर्म-कर्म

होलाष्टक पर कर लें ये काम, वास्तु दोष होगा खत्म, बढ़ेगी सुख-समृद्धि

हिंदू धर्म में ज्योतिष और वास्तु की दृष्टिकोण से होलाष्टक का खास महत्व होता है। इसे अशुभ समय के तौर पर जाना जाता है। होलाष्टक की शुरुआत होली से 8 दिन पहले होती है। इस 8 दिन की अवधि को ही होलाष्टक कहते हैं। मान्यता है कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। इसलिए इस दौरान शुभ व मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। वहीं, वास्तु शास्त्र के मुताबिक होलाष्टक से पहले कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें करने से घर में वास्तु दोष कम होता है। इसके अलावा घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चलिए वास्तु के मुताबिक जानते हैं कि होलाष्टक से पहले क्या करना चाहिए?

इस साल होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी 2026 से हो रही है और इसकी समाप्ति 3 मार्च को रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि का संबंध हिरण्यकश्यप और भक्त प्रह्लाद से जुड़ी पौराणिक कथा से है। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान ग्रहों की स्थिति थोड़ी अशुभ रहती है, इसलिए धैर्य और सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि, यह समय पूजा-पाठ, दान और भक्ति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वहीं, वास्तु की मानें, तो होलाष्टक शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम पहले पूरे न किए जाएं तो घर में नकारात्मकता और वास्तु दोष बढ़ सकते हैं।

घर से हटाएं टूटी-फूटी और बेकार चीजें- वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पड़ी टूटी, खराब वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। कई बार लोग पुरानी चीजें यह सोचकर संभालकर रख लेते हैं कि आगे काम आ सकती हैं, लेकिन इससे घर का वातावरण प्रभावित होता है। ऐसे में होलाष्टक से पहले घर की अच्छी तरीके से साफ-सफाई कर लें और टूटी-फूटी और बेकार चीजें घर से बाहर निकाल दें।

आंचलिक

संकल्प थीम वाला बजट बस्तर के समग्र विकास का रोडमैप : मंत्री केदार कश्यप

बस्तर की सिंचाई को मिलेगा स्थायी संबल, 2,024 करोड़ के प्रावधान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार

समवेत शिखर संवाददाता

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 का संकल्प थीम आधारित बजट बस्तर सहित पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक, संतुलित एवं दूरदर्शी है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस जनोन्मुखी बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह बजट केवल आयङ्व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की उन्नति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का सशक्त संकल्प-पत्र है। बस्तर के युवाओं, किसानों, आदिवासी समाज और दूरस्थ अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने की स्पष्ट सोच इस बजट में दिखाई देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, खेल, पर्यटन और आजीविका- हर क्षेत्र में संतुलित निवेश से बस्तर के विकास को नई दिशा मिलेगी। खेल एवं युवा सशक्तिकरण के अंतर्गत बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ का प्रावधान युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होगा। वहीं अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी हेतु 100 करोड़ का निवेश बस्तर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मजबूत आधार का निर्माण करेगा। बस्तरनेट परियोजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान दूरस्थ गांवों तक विश्वसनीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा। साथ ही मुख्यमंत्री बस सेवा योजना 10 करोड़ से बस्तर अंचल में आवागमन सुगम होगा और आम नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। होम-स्टे नीति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान बस्तर, सरगुजा क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। एग्रो एवं फॉरेस्ट प्रोसेसिंग निवेश अनुदान 100 करोड़ तथा बकरी, सूकर एवं मधुमक्खी पालन 15 करोड़ जैसे प्रावधान ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों

में आत्मनिर्भर आजीविका को सुदृढ़ करेंगे।

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार : स्वास्थ्य क्षेत्र में दंतेवाड़ा सहित मेडिकल कॉलेज के लिए 50 करोड़ तथा जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से बस्तरवासियों को उन्नत और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी।

सड़क और अधोसंरचना से विकास को गति : नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों की प्रमुख सड़कों एवं पुलों के लिए किए गए प्रावधानों से आवागमन, व्यापार और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी तथा विकास की रफ्तार तेज होगी।

सिंचाई और जल संसाधन से कृषि को संबल : इंद्रावती नदी पर मातनार एवं देउरगांव बैराज व 68 किमी नहर 2,024 करोड़, महादेवघाट बैराज 100 करोड़ और मद्देमारका डायवर्जन योजना 110 करोड़ जैसी योजनाएं बस्तर की कृषि को स्थायी और समृद्ध बनाएंगी।

बस्तर विकास प्राधिकरण को सशक्त समर्थन : बस्तर विकास प्राधिकरण हेतु 75 करोड़ का प्रावधान क्षेत्रीय योजनाओं के प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

विकसित छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम : मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह बजट वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए अतिरिक्त संसाधनों के सृजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह न केवल विकास की गति को तेज करेगा, बल्कि किसान, श्रमिक, युवा, उद्यमी और वनवासी-हर वर्ग के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा और बस्तर को आत्मनिर्भर, सुरक्षित व समृद्ध बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक

समवेत शिखर संवाददाता

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री आरएस विश्वकर्मा ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समन्वित पहल किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं का वास्तविक लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभागों की सेवाओं की उपलब्धता पर फोकस करें। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।

उन्होंने रोजगार एवं कौशल विकास की दिशा में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन, उद्योग विभागों को सकारात्मक प्रयास किए जाने कहा। साथ ही धरातल पर प्रदर्शित उत्कृष्ट कार्य के बारे में अन्य लोगों को अवगत करवाकर उन्हें भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान आयोग के सदस्य श्री नीलांबर नायक, श्री यशवंत सिंह वर्मा, श्री बलदाऊ राम साहू, श्री हरिशंकर यादव, श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा एवं श्री कृष्ण कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे।

आज का इतिहास

- 1788 - पिट्स रेग्यूलेट्री एक्ट पारित किया गया।
- 1921 - जार्जिया की राजधानी तिब्लिसी पर रूस ने क़ब्ज़ा किया।
- 1925 - जापान और पूर्व सोवियत संघ के बीच राजनयिक रिश्ते कायम हुये।
- 1945 - द्वितीय विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की।
- 1952 - नावें की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ।
- 1760 - लॉर्ड क्लाइव ने पहली बार भारत छोड़ा और 1765 में वापस लौटे। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के पहले गवर्नर जनरल थे।
- 1962 - देश के तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

बस्तर की लाइफ लाइन से लेकर पर्यटन तक, विकास की नई इबारत

समवेत शिखर संवाददाता

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करने वाला साबित हो रहा है। इस बजट के प्रावधानों ने न केवल राजधानी बल्कि बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों के निवासियों और व्यवसायियों में भारी उत्साह भर दिया है। बजट की बारीकियों पर गौर करें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने अधोसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए आम जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की है।

व्यवसायी श्री अनिल लुंकड़ ने इस वित्तीय योजना का पुरजोर स्वागत करते हुए इसे बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनके अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रावधान इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगे, वहीं पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा देने की नीति स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगी। यह निवेश न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करेगा।

इसी क्रम में वित्तीय विशेषज्ञ और चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री योगेंद्र कौशिक ने बजट के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दस्तावेज शिक्षा के साथ-साथ प्रदेश के अन्नदाताओं और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला है। उनका मानना है कि युवाओं के लिए किए गए विशेष आवंटन और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित योजनाएं राज्य की विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। बजट का यह संतुलित दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। बस्तर संभाग की बात करें तो व्यवसायी श्री मनीष मूलचंदानी ने आदर्श शहर समृद्धि योजना को जगदलपुर के भविष्य के लिए क्रांतिकारी बताया है। उनके अनुसार इस योजना से शहरी सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा जिसका सीधा लाभ स्थानीय नागरिकों को मिलेगा। विशेष रूप से केशकाल घाट के उन्नयन की घोषणा ने क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि यह सड़क बस्तर की लाइफ लाइन मानी जाती है और इसके सुदृढ़ीकरण से व्यापारिक परिवहन और यात्रा सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार ने बस्तर को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी बाधा दूर कर दी है, जिससे आने वाले समय में निवेश और पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना है।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य, जनसमस्याओं व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

समवेत शिखर संवाददाता

दंतेवाड़ा। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के डंकनी सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नक्सल पीड़ित परिवारों तथा आत्मसमर्पित व्यक्तियों के नियमित हेल्थ चेकअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे उनके परिवारों को भी नियमित रूप से विशेष हेल्थ कैंप आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। कलेक्टर ने जिले में आयुष्मान कार्ड, वय वंदन योजना कार्ड के लंबित हितग्राहियों को योजना से जोड़ने हेतु आयोजित विशेष शिविर के दौरान निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने को भी कहा। ताकि जिन पंचायतों में अधिक लंबित हितग्राहियों की संख्या है वहां प्लान करके एक सप्ताह में शत-प्रतिशत कार्य को पूरा हो सकें। इस क्रम में उन्होंने ''हाई रिस्क प्रेग्नेंसी'' के प्रकरणों में हितग्राहियों का चिन्हांकित कर गर्भवती

महिलाओं उनके स्वास्थ्य की पूर्व जानकारी देते हुए उनको संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा जिस ब्लॉक में संस्थागत प्रसव में कमी दर्शित हो रही है वहां विशेष रूप से फोकस करें। साथ ही उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा।

समय सीमा के एजेंडे अनुसार उन्होंने जन समस्या शिविर में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन प्रकरणों का त्वरित निराकरण संभव है, उन्हें मांग के आधार पर शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में आए सभी आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मूलभूत सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त आवेदनों की अलग से सूची तैयार की जाए, ताकि प्राथमिकता तय कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जा सके और ग्रामीणों को शीघ्र लाभ मिल सके।

इसके अलावा उन्होंने ने शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं की खरीदी केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही किये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जेम पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रशिक्षण में पंजीयन, निविदा प्रक्रिया, ऑनलाइन ऑर्डर एवं भुगतान प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद भी यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया में लापरवाही करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री ध्रुव ने शिक्षा विभाग से अपार आईडी के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आधार अपडेट, जन्म तिथि और स्कूली दस्तावेजों में कमी पेशी को दूर करने की पहल जारी रखें और जल्द अपार आईडी के काम को पूरा करवाएं। साथ ही संपूर्णता अभियान के इंडिकेटर पर चर्चा कर संबंधित विभागों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने कहा। उन्होंने खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग से चावल गोदाम की व्यवस्थाओं, चावल उत्सव की तैयारियों और राशन दुकानों में खाद्यान्न भंडारण की जानकारी ली। इसके अलावा मत्स्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, राजस्व विभाग के योजनाओं की प्रगति के साथ नक्सल पुनर्वास नीति के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली सुविधाओं और योजनाओं से लाभान्वित किए जाने के क्रम में अब तक किए गए प्रयासों की समीक्षा की।

न्यूज ब्रीफ

ऊंच-नीच की भावना की समाज को विखण्डित करती है : सत्यव्रत शास्त्री

थान खम्हरिया। देवी संपद मंडल अमरकंटक के ब्रम्हलीन स्वामी श्री शारदानंद के कृपा पात्र शिष्य सत्यव्रत शास्त्री जी महाराज वर्ष भर राम कथा सत्संग प्रवचन के

माध्यम से मानव धर्म का उपदेश देते हुए जन मानस को स्वस्थ सुखी और सम्मानित जीवन जीने की सरत ज्ञान देते रहते हैं, श्री शास्त्री जी ने अपने प्रवचन मे कहा कि समाज में ऊंच-नीच का भाव ही आपसी बैर का पैदा करता है तथा समाज को विखण्डित भी करती है इसलिए मन मे समरसता,परित्याग की भावना लेकर चलने से समाज व धर्म सुरक्षित रहती है।उन्होंने बताया कि शुद्ध सात्विक आहार से हमारे अंदर अच्छे विचार अपने आप पैदा होने लगता हैं,आज पर्यावरण तेजी के साथ प्रदुषित हो रही है जो हम सबके लिए नुकसानदायक है इसकी सुरक्षा तभी संभव है जब हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य को सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर करते रहे।शास्त्री जी ने कहा कि धर्म किसी एक के लिए नहीं है बल्कि हम सभी वर्ग के लिए है, आयोजित श्री राम कथा के माध्यम सैकडो की तादाद मे भक्त कथा सुनने पहूंच रहे है।

विधिक सेमीनार का सफल आयोजन

दुर्ग। जिला न्यायालय परिसर, दुर्ग के नवीन सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वावधान में "Speedy Trial in Civil Cases and The Succession Act" विषय पर विधिक सेमीनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सेमीनार का उद्देश्य सिविल प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में प्रभावी एवं समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श करना था। सेमीनार में आमंत्रित वक्तागण द्वारा सिविल प्रकरणों के त्वरित निष्पादन की न्यायिक कार्यप्रणाली तथा उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों पर विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। वक्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक समस्याओं तथा उनके समाधान पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने अपने संदेश में कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल निर्णय देना नहीं, बल्कि समयबद्ध एवं प्रभावी न्याय प्रदान करना है। सिविल प्रकरणों का त्वरित निराकरण न्यायपालिका की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि विलंब से पक्षकारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और न्यायालयों के प्रति विश्वास भी प्रभावित होता है। उत्तराधिकार संबंधी प्रकरणों में विधिक स्पष्टता तथा संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कल

बालोद। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 26 फरवरी को आयोजित की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद के प्राचार्य ने बताया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद में शीतल मोटर्स रायपुर द्वारा दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा एवं राजनांदगांव के लिए 26 फरवरी को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है।

बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनेक प्रावधान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिले को मिली बड़ी सौगातें

समवेत शिखर संवाददाता

कवर्धा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट में कबीरधाम जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सौगाते मिली है। बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा संसाधनों के विकास, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और आधुनिक परिवहन सुविधाओं के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिससे जिले के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

बजट प्रावधानों के तहत कुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जाएगा तथा मेडिकल कॉलेज कबीरधाम के संचालन के लिए आवश्यक सेटअप उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भी समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकेंगी और गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करने की आवश्यकता कम होगी। सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए कवर्धा-खमरिया मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लोरमी-पंडरिया रोड से सिंघनपुरी तथा रवेली रोड से जरती तक सड़क निर्माण कार्य भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में पंडरिया में नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही नालंदा लाइब्रेरी में करियर काउंसलिंग केंद्र भी स्थापित होगा। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, मार्गदर्शन और अध्ययन संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। पेयजल आपूर्ति के लिए भी बड़े स्तर पर प्रावधान किए गए हैं। सुतियापाठ जलाशय से ठाठापुर तक 54 गांवों में तथा भीरा क्षीरपानी जलाशय से 66 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला मुख्यालय में ÷सियान गुड़ी÷ को डे-केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल और सामाजिक सहभागिता का अवसर मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने के लिए कवर्धा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) स्थापित किया जाएगा। इससे ड्राइविंग टेस्ट अधिक पारदर्शी, तेज और मानकीकृत तरीके से हो सकेगा।

कबीरधाम जिले के नागरिकों ने इन योजनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा तथा वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के इस पहल से जिले के समग्र विकास को नई गति मिलेगी और लोगों की जीवनशैली में बदलाव आएगा। उनका कहना है कि यह बजट जनता के हित में उठाया गया मजबूत कदम है, जिससे आने वाले समय में जिले की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर होगी। बजट में किए गए काम हर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं और इससे आम नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा।

बजट ज्ञान के उत्थान में गति की शक्ति से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाला है: सुरेंद्र कौशिक

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। भारतीय जनता पार्टी के भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, दूरदर्शी और राज्य को समृद्ध बनाने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है।

श्री कौशिक ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। बजट राज्य की नीति को प्रदर्शन में, निवेश को परिणामों में और आकांक्षाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' को पूरा करने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक 'विकसित राज्य' बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने बजट को 'ज्ञान' और 'गति का संगम' और 'विकसित छत्तीसगढ़' का आधार स्तम्भ बताते हुए कहा कि बजट में कृषक उन्नति योजना और सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया प्रावधान यह सिद्ध करता है कि हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बिना किसी नए कर के राजस्व बढ़ाना और किसानों को समय पर इनपुट सब्सिडी देना प्रशंसनीय है। बजट में युवाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर जोर दिया गया है। 'अटल निर्माण वर्ष' के तहत बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 'महतारी वंदन योजना' के सफ ल क्रियान्वयन के साथ-साथ महिलाओं के स्वरोजगार और लखपति दीदी योजना को नई गति देना महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बजट में सड़क, बिजली और ग्रामीण विकास (गति) के लिए आवंटित भारी भरकम राशि से राज्य के सुदूर वनांचलों तक विकास की किरण पहुँचेगी। श्री कौशिक ने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधानों हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह हर छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान और समृद्धि का रोडमैप है।

विश्वास, विकास और सुशासन का बजट: राजेन्द्र पाध्ये

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। भाजपा नेता राजेन्द्र पाध्ये ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट ÷विकसित छत्तीसगढ़ 2047÷ के संकल्प को साकार करने वाला, जनआकांक्षाओं को पूरा करने वाला और सर्वांगीण विकास को गति देने वाला बजट है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में दुर्ग जिले के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भाजपा नेता राजेन्द्र पाध्ये ने कहा कि दुर्ग को अधोसंरचना, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और तकनीकी विकास के क्षेत्र में विशेष सौगात मिली है, जो जिले के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला साबित होगी।

राजेन्द्र पाध्ये ने कहा कि दुर्ग शहर के व्यस्ततम महाराजा चौक में 3 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण का प्रावधान किया गया है। इससे शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी, जाम की समस्या में कमी आएगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। दुर्ग के मोहन नगर पुलिस थाना के लिए नवीन भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है। इससे कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होगी, पुलिस प्रशासन को बेहतर संसाधन मिलेंगे और आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक वातावरण में सेवा प्राप्त होगी। दुर्ग में नए छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (सीजीआईटी) की स्थापना की सौगात युवाओं और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे आईटी एवं तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा दुर्ग डिजिटल एवं तकनीकी हब के रूप में उभरेगा। दुर्ग को मिली सौगातो का जिक्र करते हुए भाजपा नेता राजेन्द्र पाध्ये ने आगे कहा कि डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का प्रावधान महिला शिक्षा को नई ऊँचाई देगा। इससे छात्राओं को उच्च स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएँ, शोध एवं कौशल विकास के अवसर प्राप्त होंगे। बजट में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूती मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु 20 करोड़ रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है, इससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध, नवाचार और आधुनिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा तथा भिलाई तकनीकी शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत होगा। भिलाई में व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इससे स्थानीय व्यापार, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के बजट में वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की गई है : घनश्याम देवांगन

भिलाई। वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष घनश्याम देवांगन ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बजट में वरिष्ठ नागरिकों की पूरी उपेक्षा की गई है। इसे लोकलुभावन दिखाया गया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं आदि की कोई बात नहीं की गई है। केंद्र सरकार की बजट ने भी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत निराश किया है। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं सुविधाएं नहीं मिलने से वृद्धजन चिंतित एवं दुखी हैं। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार का यह रवैया समझ से परे है। बजट में पेंशन के मद में 1400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, पर यह सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के लिए है। आम वरिष्ठ नागरिकों के लिए संभवतः इसमें प्रावधान नहीं है।

खाद्यान्न में राज्य आत्मनिर्भर हो और किसानों की आर्थिक उन्नति हो ऐसा बजट में कुछ भी नहीं है: छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन

बजट से न तो उत्पादन में वृद्धि होगी और न ही उत्पादकता में सुधार होगा

समवेत शिखर संवाददाता

दुर्ग। वित्तमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, लगभग 2 घंटे से अधिक भाषण में 75 मिनट बाद कृषि का उल्लेख हुआ इससे पता चलता है कि खेती किसानी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। कृषक उन्नति योजना में पहले सिर्फ सरकार को धान बेचने वाले किसानों को शामिल किया गया था इस बार दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो कुटकी, रागी उत्पादक किसानों को भी योजना में शामिल किया गया है और इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसके अलावा नया कुछ भी नहीं है। लगता है कि सरकार उद्यानिकी फसल एवं अन्य उपज लेने वाले किसानों की उन्नति नहीं करना चाहती है। सुनिश्चित सिंचाई और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता के लिए कुछ भी नहीं है। बजट से न तो उत्पादन में वृद्धि होगी और न ही उत्पादकता में सुधार होगा। किसानों को जैविक खेती के प्रोत्साहित करने के लिए कुछ भी नहीं है, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन करने वाले और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए सिर्फ जुमले हैं। चांवल के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्न में राज्य आत्मनिर्भर और किसान स्वावलंबी बने इसके लिए बजट में कोई दिशा नहीं है।

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर
मामले की श्रेणी-राजस्व

संदर्भः- जिला-रायपुर तहसील-अभनपुर पहनं. 00026 नायकबांधा ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक -आरडी202526441630700018

// ईश्तहार//

तहसील अभनपुर के पहनं. 00026 के अंतर्गत ग्राम नायकबांधा के वर्तमान भूमिस्वामी बसंतीबाई जौ. धनसाय पिता/पति-पता सा. देह के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 382(0.0500) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता पुनीत देशलहरे पिता/पति गोवर्धन देशलहरे पता-दौहान पारा वार्ड नं. 19 ग्राम नायकबांधा तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरुस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 27.02.2026 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय तहसील अभनपुर पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/ आममुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19.02.2026 को जारी किया जाता है।

मुहर

तहसीलदार
अभनपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार //

ग्राम गोतियारडीह

रा.प्र.क्र. RD 20252644163070000
अ/6 वर्ष 2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक छन्नूलाल बघेल पिता स्व. भीषम प्रसाद बघेल निवासी ग्राम बड़े उरला, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर द्वारा गोतियारडीह प.ह.नं. 26 रा.नि.म. अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि ख.नं. 83, 1032/3, 1032/7 रकबा क्रमशः 0.100, 0.128, 0.228 हे. भूमि राजस्व अभिलेख मालती बाई पिता उधोप्रसाद के नाम पर दर्ज है। भूमि स्वामी मालती बाई पिता उधोप्रसाद की दिनांक 03.12.2025 को मृत्यु हो गई है। अतः उक्त भूमि से मृतक का नाम खाता से विलोपित कर उनके विधिक वारिसानों के नाम पर फौती दर्ज करते हुए नामांतरण किये जाने बाबत आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बी-1 की प्रति के साथ प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 27/02/2026 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 03/02/2026 को जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
अभनपुर

न्यायालय तहसीलदार अभनपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

// ईश्तहार //

ग्राम उरला

रा.प्र.क्र. RD 20252644163070000
अ/6 वर्ष 2025-26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक छन्नूलाल बघेल पिता स्व. भीषम प्रसाद बघेल निवासी ग्राम बड़े उरला, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर द्वारा ग्राम बड़े उरला प.ह.नं. 23 रा.नि.म. अभनपुर, जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि ख.नं. 798/34, 98, 512, 559/1, 593/7 रकबा क्रमशः 0.02, 0.117, 0.384, 0.316, 0.368 हे. भूमि राजस्व अभिलेख मालती बाई पिता उधोप्रसाद के नाम पर दर्ज है। भूमि स्वामी मालती बाई पिता उधोप्रसाद की दिनांक 03.12.2025 को मृत्यु हो गई है। अतः उक्त भूमि से मृतक का नाम खाता से विलोपित कर उनके विधिक वारिसानों के नाम पर फौती दर्ज करते हुए नामांतरण किये जाने बाबत आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बी-1 की प्रति के साथ प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/समूह को दावा आपत्ति हो तो वे अपना दावा आपत्ति आवेदन इस न्यायालय में नियत पेशी तारीख 27/02/2026 तक न्यायालयीन समय में स्वतः अथवा अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। नियत तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 03/02/2026 को जारी किया गया।

मुहर

तहसीलदार
अभनपुर

संपूर्णता अभियान 2.0 के लक्ष्यों के पूर्ति के लिए विभाग करें फोकस: कलेक्टर वर्मा

प्रतिमाह 07 तारीख तक चावल भंडारण के साथ वितरण प्रारंभ करने के दिए निर्देश

समवेत शिखर संवाददाता

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष मे समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर श्री वर्मा ने बैठक के दौरान संपूर्णता अभियान 2.0 की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने आकांक्षी विकासखंड बोड़ला में निर्धारित सभी 6 इंडिकेटर को शत प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य पूर्ति के लिए तेजी से कार्य आगे बढ़ाएं और फील्ड पर प्रगति की नियमित समीक्षा करें।

कलेक्टर श्री वर्मा ने खाद्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी राशन दुकानों में माह के चावल वितरण के लिए पर्याप्त भंडारण अविलंब कराएं। भंडारण के साथदृसाथ चावल वितरण भी करते जाएं। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि चावल वितरण प्रतिमाह 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से चावल उत्सव के साथ प्रारंभ हो जाए। कलेक्टर श्री वर्मा ने पीएम जनमन योजना के तहत बन रहे आवास निर्माण को ब्लाकवार समीक्षा करते हुए सभी सीईओ जनपद पंचायतों से कहा कि जितने भी हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हैं किंतु निर्माण अब तक अप्रारंभ है उन्हें तत्काल शुरू करवाया जाए। इसके लिए आवास मित्रों के माध्यम से उनसे संपर्क किया जाए। सीईओ जनपदों ने बताया कि अभी आवास निर्माण में तेजी आई है। जहां कम शुरू नहीं हुए हैं वहां विशेष फोकस करते हुए कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। लक्ष्य है कि जल्द से जल्द सभी आवासों का निर्माण शुरू करवाकर कार्य पूर्ण करा लिया जाए।

कलेक्टर श्री वर्मा ने शासन के निर्देशानुसार पीएम श्री स्कूलों के संचालन के मूल्यांकन के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों का निरीक्षण कर बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जिसमें निर्माणाधीन छात्रावास भवनों के स्थिति के बारे में निर्माण एजेंसीज के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि वय वंदन कार्ड निर्माण भी लक्ष्य के अनुसार तेजी से बनाए जाएं। कलेक्टर श्री वर्मा ने पीएम सूर्यघर योजना के रजिस्ट्रेशन के साथदृसाथ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का कार्य पूरी तेजी से करने के निर्देश बैठक में दिए।

कलेक्टर श्री वर्मा ने आगामी जनगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार जनगणना का कार्य प्रारंभ होने का रहा है। उसके पूर्व सभी संबंधित लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए आगामी 27 और 28 फरवरी को ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। जिसमें सभी सम्बंधित विभागों प्रशिक्षण लेना है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक अग्रवाल, एडीएम श्री विनय पोयाम, अपर कलेक्टर श्री नरेंद्र पैंकरा सहित सभी एसडीएम व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम-उरला, पो-बी.एम.वाय. चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/4180/छगदुमस/क्रय/2026 दिनांक 24/02/2026

कॉन्फ्रेन्स रूम फर्नीसिंग कार्य हेतु निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुख्य डेयरी संयंत्र, उरला के प्रशासनिक भवन में कॉन्फ्रेन्स रूम फर्नीसिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.03.2026 निर्धारित है। ईच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाईटः- www.cgcoopdairyfed.in से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम-उरला, पो-बी.एम.वाय. चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/4178/छगदुमस/क्रय/2026 दिनांक 24/02/2026

स्टोर रूम निर्माण कार्य हेतु निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुख्य डेयरी संयंत्र, उरला में स्टोर रूम निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.03.2026 निर्धारित है। ईच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाईटः- www.cgcoopdairyfed.in से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित
ग्राम-उरला, पो-बी.एम.वाय. चरोदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/4176/छगदुमस/क्रय/2026 दिनांक 24/02/2026

प्रशासनिक कार्यालय के विद्युतीकरण सुधार कार्य हेतु निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा मुख्य डेयरी संयंत्र, उरला में स्थित प्रशासनिक भवन में विद्युतीकरण सुधार-नये वायरिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 19.03.2026 निर्धारित है। ईच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र दुग्ध महासंघ की वेबसाईटः- www.cgcoop-dairyfed.in से प्राप्त कर सकते हैं।

प्रबंध संचालक

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल फोन : 8057766078

ई-नीलामी सूचना

परिशिष्ट - IV क [नियम 8(6) एवं 6(2) का परन्तुक देखें]

चल/अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 6(2) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित अचल संपत्तियों के ऋणियों एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का उसके **कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय दिनांक **18/03/2026** को **केनरा बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के बकाया राशि को वसूल करने हेतु "जैसा है जहां है, जो है जैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा एवं खाते/ जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि
ऋणी-**मेसर्स मॉडर्न साइंटिफिक कंपनी** प्रोपराइटर- इमरान उमरानी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल गफ्फार उमरानी, स्टेशन रोड रायपुर, छत्तीसगढ़ -492009 जमानतदारः रफीक उमरानी पुत्र अब्दुल गफ्फार उमरानी	भूमि एवं भवन स्थित प्लाट नं. 26, समता सहकारी गृह निर्माण सहकारी समिति, समता कॉलोनी, रायपुर, क्षेत्रफल-4000 वर्गफीट संपत्ति मालिक- अब्दुल गफ्फार उमरानी प्लाट क्षेत्रफल 4000 वर्गफिट में से 921 वर्गफिट दरबार है। BAANKNET PROPERTY ID: CNRBMODERNSCIENTIFIC COORDINATES: 21.1455, 81.3708 सांकेतिक कब्जा	05/05/2022 / 15/07/2022 / दि. 23/02/2026 को ₹ 97,67,173.73/- + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	₹ 1,09,50,000/- / ₹ 10,95,000/- / ₹ 10000/-

धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 17/03/2026 या उससे पूर्व सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 18/03/2026, दोपहर 12.00 से दोपहर 2.00 बजे तक (5 मिनिट के असीमित विस्तार पर)

(1) इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य की 10% अग्रिम राशि (ईएमडी) सीधे मेसर्स पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड (baanknet.com) पोर्टल के ई-वॉलेट में जमा करनी होगी या चालान जनरेट करके बोली जमा करने की उपरोक्त तिथि को उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करनी होगी।
(2) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बिक्री होने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त अनुसार बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
(3) सभी शुल्क, स्टांप शुल्क/जीएसटी पंजीकरण शुल्क आदि, जैसा लागू हो और कोई भी कर, राजस्व/किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को बकाया आदि केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
(4) यहां संपत्ति का विक्रय राशि रु. 50 लाख या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1% टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी।

विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबपोर्टल http://BAANKNET.com देखें अथवा सम्पर्क करें- मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, स्पेशलाइज्ड, ए.आर.एम. शाखा, प्लाट नं. 4, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल 8989014648, 8057766078, 9691096410, 9123403299 (भोपाल), 7905027805 (जबलपुर एवं बिलासपुर), 7683068902 (रायपुर), 9140476074 (ग्वालियर), 9830130770 (इंदौर), 8073562754 (BHOPAL)

दिनांक : 23.02.2026, स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

न्यूज ब्रीफ

क्रिकेट स्पर्धा में शामिल हुए नपाध्यक्ष

महासमुंद। सिरपुर क्षेत्र के ग्राम खिरसाली में ग्रामीण युवाओं द्वारा भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने प्रेरित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह के आयोजनों से गाँव के प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौक मिलता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को आपसी सामंजस्य व भाईचारे की भावना के साथ खेलने की बात कही। इस अवसर पर टीम के कप्तान मोहित ध्रुव, उप कप्तान दुर्जन बरिहा, राकेश बरिहा, योगेश बरिहा, संजू विश्वकर्मा, उमेंद्र पटेल, रूपेश पटेल, गितेश पटेल, दीपक पटेल, गंगाराम ध्रुव, भगत बरिहा, मिलन बरिहा, अजित बरिहा, रोशन दीवान, टनेश्वर बरिहा, हेमसागर कर्ष, महेश्वर कर्ष, विशाल ध्रुव, सरगम ध्रुव, हिमांशु पटेल, अमित ध्रुव आदि उपस्थित थे।

किसानों को बिजली के लिए फिर रुलाना शुरू कर दिया भाजपा ने : अंकित

बागबाहरा। कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा ने बताया कि खरीफफसल में यूरिया, बीज, पंजीयन, मौसम की मार से कम फसल और अंत मे धान खरीदी में तरसाने के बाद अब जब किसान रबी फसल लगाने की ओर अग्रसर हैं तो उन्हें केसीसी में परेशान किया। अंकित ने बताया कि अभी जब गर्मी शुरू नहीं हुई है तो बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। पिछले 2 सालों से किसानों के पंप कनेक्शन की लाईन अलग करने के बाद रोजाना लाईन गोल, लो वोल्टेज,फेस चेंज की समस्या पुनः शुरू हो चुकी है और रोजाना कम से कम 20 फोन बिजली समस्या को लेकर अभी से आना शुरू हो चुका है। अंकित ने बताया इस बार किसान स्वयं भी जागरूक हो कर कई मर्तबा ज्ञापन बिजली विभाग को सौप चुका है उसके बावजूद लो वोल्टेज की समस्या सुधरने का नाम ही नही ले रही है। अंकित ने कहा कि जबसे काँग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ से गई है तब से भाजपा सरकार ने किसानों, व्यापारियों, मजदूरों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जीएसटी के नाम पर छापे, धान पर छापे पर दिन प्रतिदिन शराब की अवैध बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है और विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है।

छग को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने वाला बजट : विधायक

बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2026. 27 का बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष बजट का आकार एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2026.27 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का संकल्प है। इस बजट से विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बजट के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। बजट के संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा है कि यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट है। यह नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार ने कई प्रमुख घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट . छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 के लक्ष्यों की पूर्ति एवं राज्य की सतत् विकास यात्रा में उठाया गया एक कदम है। हमारी सरकार ने पहले बजट में ज्ञान उत्थान की आधारशिला रखी, वहीं दूसरे बजट में गति की रणनीति से प्रदेश के समग्र विकास को तीव्र करने की बात कही गई थी।

वर्तमान बजट संकल्प थीम पर आधारित है। इसका अर्थ समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाईवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक है। इस बजट में अलग अलग विभागों के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग हेतु 22360 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास हेतु 16560 करोड़, कृषि हेतु 13507 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु 12820 करोड़, महिला एवं बाल विकास हेतु 11000 करोड़, लोक निर्माण हेतु 9451 करोड़, ऊर्जा हेतु 9015 करोड़, गृह विभाग हेतु 8380 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु 8050 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु 3890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में नई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। इनमें विकसित भारत जी राम जी योजना, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री दूरुतगामी सड़क संपर्क योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, कैशलैस चिकित्सा सुविधा, सीजी वायु, रानी दुर्गावती योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, लखपति दीदी भ्रमण योजना, मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना, छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक सहायता हेतु योजना शामिल है।

बजट जनाकांक्षाओं के विपरीत, 5 सौ रुपए में रसोई गैस देने के वादा पर अमल नहीं : विनोद

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। पूर्व संसदीय सचिव विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट को केवल मोदी के तारीफें का पुलिंदा बताते हुए जन आकांक्षाओं के विपरीत व प्रदेश वासियों को निराश करने वाला निरूपित किया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि बजट में विधान सभा चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं का जिक्र नहीं किया गया है। महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस, बेरोजगार युवाओं से किए वादे को बजट में नजर अंदाज किया गया है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई है। 33 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। बीएड अभ्यर्थी और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, परंतु बजट में उनकी समस्याओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। प्रदेश के दैवेभो कर्मियों को नियमित करने का वादा था। कर्मचारी आशान्वित थे कि उनकी नियमितीकरण को लेकर विशेष पहल होगी। लेकिन, उन्हें भी निराश किया गया। महाविद्यालयीन छात्राओं को मासिक ट्रेवलिंग अलाउंस देने का वादा कर सरकार बनाने वाली भाजपा की साय सरकार ने तीसरे बजट में भी कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। विश्व विख्यात सिरपुर को राष्ट्रीय पटल पर सामने लाने विशेष घोषणाएं नहीं होने से उपेक्षित रहा। सिरपुर विकाश प्राधिकरण को अलग से राशि जारी न कर सरकार ने सिरपुर के ऐतिहासिक महत्ता को नजर अंदाज किया है। खेतिहर भूमिहीन किसानों के लिए जितनी राशि का प्रावधान किया गया हैए वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। प्रदेश में 500 नई मोबाइल टावर लगाने का प्रावधान कर साय सरकार ने उद्योगपति मित्रों का विशेष ध्यान रखा। जबकि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं, महिलाओं के हितों को पूरी तरह दरकिनार किया है। यह बजट पूरी तरह निराश करने वाला प्रदेश वासियों की हितों पर कुठाराघात है।

बजट में बैराज के लिए 390 करोड़, विकास के लिए 36 करोड़ से सिरपुर का होगा कायाकल्प

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। सिरपुर विकास के लिए बजट में प्रावधान करने से विकास को गति मिलने के साथ ही सिरपुर का कायाकल्प होगा बल्कि ऐतिहासिक नगरी सिरपुर के लिए पर्यटक आकर्षित होंगे। उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति में ग्राम पंचायत सिरपुर के उप सरपंच राजेश सिंह ठाकुर ने कही। उन्होंने सीएम विष्णुदेव राय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी व स्थानीय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक के प्रयास से बजट में प्रावधान शामिल किया गया है। 36 करोड़ की स्वीकृति सिरपुर के विकास के लिए बजट में प्रावधान किया गया है जिससे ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, महानदी तट में रिवर्ट फ्रंट, नवीव सड़क एवं अन्य विकास कार्य शामिल है। इसी तरह मुहमेला सिरपुर बैराज के लिए 390 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। बैराज बनने से जहां किसानों को लाभ मिलेगा वही वाटर लेबल भी क्षेत्र में बढ़ेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि सिरपुर प्रवास के दौरान विधायक श्री सिन्हा ने इन सभी परियोजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देते हुए कहा था कि विकास के लिए सिरपुर किसी का मोहताज नही रहेगा। पर्यटन विकसित होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा।

बजट निराशाजनक : रश्मि चंद्राकर

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। बजट प्रतिक्रिया देते हुए महासमुंद कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि बजट भाषण लंबा और बेहद निराशाजनक रहा। बीजेपी सरकार का संकल्प धरा का धरा रह जाएगा। बजट के माध्यम से केवल सपना दिखाया गया है डॉ रश्मि चंद्राकर के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किसान हैं, लेकिन प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद प्रावधान नजर नहीं आते। डॉ रश्मि चंद्राकर ने भाजपा सरकार से किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और धान खरीद प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने की मांग की है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके। इसके साथ ही डॉ रश्मि चंद्राकर ने सरकार पर किसानों को उनकी मेहनत का एक एक दाना धान खरीदी नहीं करने पाने का आरोप भी लगाया और कहा कि किसान लगातार परेशान हैं, लेकिन बजट में उनकी चिंता दूर करने के लिए कुछ खास नहीं है। मोदी की गारंटी में 500 रु में गैस सिलेंडर देने का का वादा था जिसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। बढ़ती महंगाई को कम करने का कोई रोड मैप नहीं है । छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ठग कर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट भाषण में महतारी वंदन योजना से वंचित महिलाओं के लिए फिर से फार्म भरने के लिए पोर्टल को खोलने की कोई जिक्र नहीं की गई। शिक्षा ही देश का भविष्य तय करती है, लेकिन इस बजट में गरीब परिवार के बच्चो को नर्सरी शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पहले आरटीई के माध्यम से नर्सरी शिक्षा निशुल्क शिक्षा दिया जाता था जिसे बंद कर कक्षा पहली से कर दी गई हैं इस से गरीब परिवार के बच्चो को नर्सरी शिक्षा के लिए भारी भरकम खर्च करना पड़ेगा भाजपा सरकार गरीब परिवार के बच्चो को शिक्षा से वंचित रखना चाहती हैं।

संकाय विकास कार्य पर दी जानकारी

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। पाँच दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 24 फरवरी को हाइब्रिड माध्यम ;ऑनलाइन एवं ऑफ्लाइनद्ध में किया गया। यह कार्यक्रम आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ आईक्यूएसीद्ध के तत्वावधान में तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार एवं नेतृत्व के क्षेत्र में सभी लिंगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, लिंग आधारित भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करना, समान कार्य हेतु समान वेतन को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षित, सम्मानजनक एवं उत्पीड़न.मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य करुणा दुबे उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्राओं को पुरानी सोच से आगे बढ़ते हुए जागरूकता एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस बी कुमार ने की। उन्होंने स्वागत भाषण में संकाय विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं का उल्लेख किया तथा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। प्रथम दिवस की मुख्य वक्ता डॉ आराधना शुक्ला, सहायक प्राध्यापक रायपुर ने श्महिलाएं एवं वित्तीय नेतृत्वरू आर्थिक नीति निर्माण में उनकी भागीदारी एवं सशक्तिकरण विषय पर व्याख्यान दिया। आमंत्रित वक्ता डा निधि सिंह शुक्ला ने सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं के योगदान, नेतृत्व क्षमता एवं अदम्य साहस का उल्लेख किया, महिला सशक्तिकरण और टेक्नोलॉजी व योजनाओं का उल्लेख किया।। कार्यक्रम का संचालन डा. स्वेतलाना नागल द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के संरक्षक डॉ शीलभद्र कुमार, प्रभारी प्राचार्य एवं संयोजक डॉ सरस्वती वर्मा विभागाध्यक्ष, हिंदी तथा समन्वयक डॉ स्वेतलाना नागल विभागाध्यक्ष सूक्ष्मजीव विज्ञान के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन टीम में ओमप्रकाश पटेल विभागाध्यक्ष, भूगोल, डॉ मनोज कुमार शर्मा विभागाध्यक्ष वाणिज्य, अजय कुमार श्रीवास पुस्तकालयाध्यक्ष सहित प्राध्यापक गण ओंकार साहू, जगदीश प्रसाद खटकर, वंदना यादव,अरविंद साहू, कविता गहीर, खगेश्वर नवरांगे आदि का योगदान रहा।

नपाध्यक्ष ने सम्पत्ति कर, जलकर सहित अन्य कर वसूली की समीक्षा की

समवेत शिखर संवाददाता

बागबाहरा। नगर पालिका परिषद बागबाहरा कार्यालय में सोमवार को नगर पालिकाध्यक्ष श्रीमती खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल ने सम्पत्ति कर, जलकर और सहित अन्य कर वसूली की समीक्षा की। सभी करो की वित्तीय वर्ष के वार्डवार वसूली की जानकारी ली गई। कम वसूली के लिए राजस्व प्रभारी को सभी बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नगर पालिका परिषद प्रशासन ने टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है. व उनके नाम सार्वजनिक करने हेतु आदेशित किया वार्ड 1 से 15 तक घूम रही राजस्व की टीम नगर पालिका परिषद बागबाहरा के वार्डों से संपत्ति कर को लेकर नगर पालिका ने कई बार लोगों से अपील की कि संपत्ति कर समय पर जमा किया जाए. लेकिन नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक अधिकांश घरों में सम्पत्ति कर, समेकित कर और जल शुल्क की बड़ी बकाया राशि लंबित है।

नगर पालिका के अनुसार बकायादारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर कर भुगतान के लिए अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने कर जमा नहीं किया है। अब नगर पालिका परिषद बागबाहरा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। नगर में लगभग 2255 घरों में पानी का कनेक्शन है। जिन पर लगभग चालु वर्ष में 29 लाख रुपया बकाया है। वहीं पिछले साल का 50 लाख की वसूली बकाया है इसी तरह संपत्ति कर 37लाख व समेकित कर 39 लाख. रुपये की बकाएदारी चल रही है। टैक्स जमा करने के लिए एनडीएस ऐप बनाया गया है। ऐप माध्यम से आप घर बैठे मोबाइल से अपना गृहकर-जलकर जमा कर सकते हैं।

बकायादारों को आखिरी मौका

नगर पालिका परिषद बागबाहरा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी गिरीश कुमार चंद्रा ने बताया कि वार्ड में नगर पालिका की टीम की ड्यूटी लगाकर वसूली करवाई जा रही है. मुनादी कराकर संपत्ति, समेकित, दुकान और जल कर जमा करने को कहा जा रहा है. जमा नहीं करने वालों को चिन्हांकित कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी वार्ड नंबर 1 से 15 तक वसूली अभियान चलाने के लिए नगर पालिका की राजस्व टीम का गठन किया गया।

गुटखा माफिया के यहां खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई, 9 बोरी गुटखा जब्त

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने स्थानीय गंजपारा में औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। टीम द्वारा फर्म मेसर्स मनभावन एजेंसी गंजपारा महासमुंद एवं फर्म मेसर्स हरीश जनरल स्टोर गंजपारा महासमुंद का आकस्मिक जांच किया गया। जांच के दौरान टीम ने मेसर्स मनभावन एजेंसी से 08 बोरी पान पसंद कुल 276 पैकेट संभावित गुटखा जब्त अभिगृहितद्ध किया। वहीं मेसर्स हरीश जनरल स्टोर से 01 बोरी प्यान पसंद संभावित गुटखा सीज किया गया। कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रोशनी राजपूत एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई द्वारा विधिवत नमूना संकलित किया गया। अभिहित अधिकारी उमेश वर्मा ने बताया कि जब्त किए गए नमूनों को परीक्षण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पंचायतों का विकास भाजपा की प्राथमिकता से बाहर : सृष्टि

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। जिला पंचायत सदस्य सृष्टि अमर चंद्राकर ने कहा कि त्रि.स्तरीय पंचायत चुनाव के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पंचायतों के खाते खाली पडे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की साय सरकार में पंचायतें बेहाल हो चुकी है। सरकार का जो रवैया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि गाँवों का विकास भाजपा सरकार की प्राथिमकता से बाहर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 2 वर्ष से अधिक तथा पंचायत चुनाव को एक वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन ग्रामीण विकास की बुनियाद कही जाने वाली पंचायतें आज इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। गांवों के विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंचायतों के बैंक खाते खाली पड़े हैं और विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं। राज्य की ग्राम पंचायतें आज आर्थिक बदहाली का शिकार हैं। पंचायतों में कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। सृष्टि ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने न तो पंचायतों के लिए कोई बड़ी योजना शुरू की, और न ही पिछली सरकार के कार्यकाल की 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि को जारी करने की कोई पहल की। नतीजा यह है कि पंचायतें सिर्फ नाम की रह गई हैं, जबकि फैसले और फंड राजधानी की फाइलों में कैद हैं। पंचायत चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधि केवल नाम का रह गया है। सरपंचए पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य केवल डमी बनकर रह गया है। राशि नहीं होने से पंचायतों के विकास में जनप्रतिनिधि अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। सरपंच, पंच अपने गाँवों के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं।

पूर्व में महासमुंद ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों ने 15 वें वित्त की राशि की मांग को लेकर धरना . आंदोलन किया था, जिसके बाद साल में 4 बार किश्तों में मिलने वाली 15 वें वित्त की राशि का केवल एक किश्त पंचायतों को मिला था। लेकिन उक्त राशि का भी टेक्निकल कारणों से आहरण पर रोक लगा दिया गया है।

कलेक्टर ने किया स्वामी आत्मानंद स्कूल तुमगांव का निरीक्षण

बच्चों से की ट्रैफिक सिग्नल पर चर्चा

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल तुमगांव का सघन निरीक्षण एवं अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय परिसर, कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर लैबए पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। जिसमें सैचुरेशन के 21 बिंदुओं को एक.एक पॉइंट विषयवार निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री लंगेह ने कक्षा छठवीं के बच्चों के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर चर्चा करते हुए हेलमेट की उपयोगिता सीट बेल्ट बांधना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग न करने पर विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर ने खेल के महत्व के बारे में भी बच्चों को समझाया तथा पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रिवीजन को आवश्यक आवश्यक बताते हुए बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने तथा मोबाइल की उपयोगिता को कम करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के साथ चर्चा के दौरान पढ़ाई के महत्व को समझाते हुए कहा कि जो चीज समझ में नहीं आता उसे बार.बार पढ़ा जाए पूछा जाए और उसको सीखने की कोशिश की जाए तो वह दो से तीन बार में समझ में आने लगेगी। इंग्लिश रीडिंग के साथ हिंदी में समझ भी आना चाहिए। कलेक्टर ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों में टीएलएम बल फैचर्स, जादुई पिटारा एवं पीयर लर्निंग के माध्यम से अधिक से अधिक गुणवत्ता सुधार करने का प्रयास किए जाए। इस दौरान उन्होंने पीएम श्री तुमगांव में चल रहे निर्माण कार्य की भी समीक्षा किया और जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाकर मार्च तक पूर्ण करने निर्देशित किया गया। उन्होंने पीएम श्री योजना अंतर्गत निर्धारित विभिन्न मानकों एवं घटकों जैसे स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा, इंटरनेट सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय, एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, खेल सुविधाएं, ग्रीन स्कूल फीचर्स, नवाचार परिषद, ईको क्लब, शिक्षक क्षमता संवर्धन, टीएलएम का उपयोग, करियर काउंसलिंग, बालिका सुरक्षा प्रशिक्षण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, छात्र उपस्थिति ट्रैकिंग, आईडी कार्ड वितरण एवं बैगलेस डे आदि को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

बाल बैडमिंटन खेल के लिए मुरली का चयन

पिछले कई वर्षों से अपने खेल कौशल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं

समवेत शिखर संवाददाता

महासमुंद। भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वाधान में इनडो मलेशिया टेस्ट सीरीज पुरुष एवं महिला का आयोजन मलेशिया में 27 फरवरी से 04 मार्च तक आयोजित किया गया हैं। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से चार खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। पुरुष वर्ग में मुरली सिंह राजपुरोहित महासमुंद, बंटी चंद्रवंशी तथा महिला वर्ग में क्षमानिधी एवं लता साहू शामिल होंगे। पिछले कई वर्षों से अपने खेल कौशल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। मुरली सिंह राजपुरोहित पिता मोती सिंह राजपुरोहित जो भैरव बीकानेर स्वीट्स के संचालक के पुत्र है। तथा माता रामी देवी राजपुरोहित है। प्रदेश सह सचिव अंकित लूनिया के मार्गदर्शन में कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, सेंट्रल जोन, स्कूल एवं ओपन नेशनल खेल में शामिल हो चुके है। मुरली सिंह राजपुरोहित ने लगातार 4 वर्षों से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भागीदारी करते आ रहे हैं। 2019-20 एवं 2021.2022 में सेंट्रल जोन प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। 2 राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता में भागीदारी 2 सब-जूनियर नेशनलए 2021 में जूनियर नेशनलए 2023 में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में भागीदारी निभाई है। मुरली सिंह राजपुरोहित के इंडो मलेशिया टेस्ट सीरीज में चयन होने पर जिला अध्यक्ष भाजपा येतराम साहू, बादल मक्कड, आनंद साहू, महेंद्र सिक्का, राहुल चंद्राकर, भारतीय बॉल बैडमिंटन संघ महासचिव वाई राजा राव, छत्तीसगढ़ बॉल बैडमिंटन कार्यकारी अध्यक्ष इसरार अहमद, खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण महासमुंद मनोज कुमार धृतलहरे, समस्त जिला सचिवों छत्तीसगढ़, प्रदेश सह सचिव एवं जिला सचिव अंकित लुनिया, नरेश चंद्रकर, मोबिन कुरैशी, राकेश थावाईति, रविंदर गुरुदत्त, तारिणी चंद्राकर, सेवन दास मानिकपुरी, लोकेश चंद्राकर, दिलीप कुमार लहरें, प्रभात सेठ, राजेश शर्मा, विनय भारद्वाज, भूषण, गजेंद्र यादव, रमन सिंह ठाकुर,इमरान अली,अभिषेक आदि ने बधाई दी है।

न्यूज ब्रीफ

अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री बने सीटू भाटिया

खरोरा। शहर में हर्ष का माहौल उस समय देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा में

सक्रिय कार्यकर्ता सीटू भाटिया को जिला मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। जिला मंत्री बनाए जाने पर कई प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तित्वों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। शुभकामना देने वालों में अंजय शुक्ला, टुम्पा घोष ,श्याम अग्रवाल ,नन्हे भैया, संदीप छाबड़ा , भूपिंदर सलूजा, राशिद अली, लालू पंसारी, अर्णव शर्मा, हरबजन सिंह, सजल भाटिया, तरयंश भाटिया, भवदीप भाटिया, मलकीत भाटिया, युवराज सिंह ,अर्शदीप सिंह ,नवजोत सिंह सिद्धू ,शुभमंगिल ,जसप्रीत समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे। सभी ने विश्वास जताया कि सीटू भाटिया अपने नए दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पिछले बजटों की पुनरावृति है यह बजट : विद्रोही

फिंगेश्वर। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) छत्तीसगढ़ के प्रदेश

महासचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि पिछले बजट में कृषि अनुदान, धान खरीदी और ग्रामीण अधोसंरचना पर जो घोषणाएँ की गई थीं, उनमें से कई अधूरी रहीं। वर्तमान बजट में उन्हीं योजनाओं को पुनः पैकेजिंग कर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन नई संरचनात्मक पहल का अभाव है। वास्तविक निवेश की वृद्धि मुद्रास्फीति की दर की तुलना में नगण्य है, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, राज्य सरकार किसानों को धान पर 3286 रूपये प्रति क्विंटल की दर अंतर की राशि देने बजट में प्रावधान नहीं किया है जिससे किसनो को प्रति एकड़ करीब चार हजार रूपये नुकसान होगा। कृषि लागत (डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी) में लगातार वृद्धि हुई है। यदि वास्तविक लागत की तुलना समर्थन मूल्य से की जाए, तो किसानों का लाभांश घटता हुआ दिखाई देता है। बजट में लागत नियंत्रण के ठोस उपायों का अभाव है। सिंचाई विस्तार की घोषणाएँ वर्षों से की जाती रही हैं, परंतु वास्तविक सिंचित रकबा अपेक्षित गति से नहीं बढ़ा। इस बजट में भी नई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की तुलना में रखरखाव पर अधिक बल है। जल संकट और वर्षा पर निर्भरता की समस्या का दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया।

निधन

श्रवण नेताम

भाटापारा। स्थानीय थाना में पदस्थ उपनिरीक्षक श्रवण नेताम का हृदय आघात से निधन हो गया। उनके निधन पर नगर निरीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य लोगो ने गहरा शोक प्रकट किया है व नेताम को श्रद्धांजली दी है।

रविशंकर जायसवाल

भाटापारा। डडसेना कलार समाज के वरिष्ठ नागरिक सुखनंदन जयसवाल के ज्येष्ठ पुत्र रविशंकर जयसवाल का आकष्मिक निधन हो गया उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रविशंकर जयसवाल पत्रकार कैलाश जयसवाल एवं तुलसी जयसवाल के बड़े भाई थे।

समूह की महिलाएं पलास, चुकंदर एवं पालक के पत्तों से बना रही हर्बल गुलाल

इस बार प्राकृतिक रंगों से रंगीन होगी होली

समवेत शिखर संवाददाता

गरियाबंद। जिले में रंगों के त्योहार होली को स्वसहायता समूह की महिलाएं इस बार और खास बना रही है। होली के त्योहार को प्राकृतिक रंगों से मनाने के लिए महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही है। ग्राम सढ़ौली की राखी महिला ग्राम संगठन की 10 सक्रिय महिलाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत हर्बल गुलाल का निर्माण कर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं पलाश से पीला, चुंकदर से लाल और पालक के पत्तों से हरा रंग निकालकर मक्के की सूखी डंठल से प्राप्त अरारोट पाउडर में मिलाकर प्राकृतिक गुलाल का निर्माण कर रही है। इसमें हानिकारक रसायनिक तत्वों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता।जिससे हर्बल गुलाल त्वचा एवं सेहत के लिए सुरक्षित रहता है। राखी महिला ग्राम संगठन की ये महिलाएँ न केवल होली के त्योहार को प्राकृतिक और सुरक्षित बना रही हैं, बल्कि अपनी आजीविका को भी मजबूत कर रही हैं।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है।कलेक्टर बीएस उइके एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने भी इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज महिलाएं स्वरोजगार सृजित कर आत्मनिर्भर बन रही है और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है। पीआरपी मीना साहू ने बताया कि पिछले वर्ष

भी बिहान समूह के दीदियों द्वारा कुल 30 हजार रूपये से अधिक की बिक्री कर लगभग 10 हजार रूपये से अधिक की शुद्ध मुनाफा अर्जित की थी।

समूह की महिलाओं से चर्चा के फलस्वरूप पारंपरिक तरीकों से बनाए गए प्राकृतिक गुलाल से न केवल सेहत स्वस्थ रहेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए आमदनी का नया स्रोत भी बन रहा है। पिछले वर्ष हर्बल गुलाल की मांग अधिक रही,जिसे देखते हुए इस बार महिलाओं ने रंग बनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने बताया कि गुलाल बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे तैयार करने में फूलों और पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। विभिन्न रंग बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है गुलाबी रंग के लिए चुकंदर और गुलाब की पंखुड़ियां, पीला रंग के लिए हल्दी और गेंदे के फूल, हरा रंग के लिए पालक व मेंहदी के पत्ते, नीला रंग के लिए अपराजिता के फूल और लाल रंग के लिए टेसू के फूलों का इस्तेमाल कर रही है।

समूह में पीआरपी मीना साहू,समूह की अध्यक्ष ललिता काशी,सचिव लक्ष्मी शांडिल्य,कोषाध्यक्ष ओमसाहू,सदस्य गुंजा ध्रुव,संतोषी चौधरी,सुरेखा चंद्रवंशी,भोजेश्वरी ध्रुव,नुतन शांडिल्य,गितेश्वरी कश्यप,जितेन्द्री मुर्रा प्राकृतिक संसाधनों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं।जंगलों से पलाश के फूलों से पीला,चुकंदर एवं गुलाब के फूलों से लाल और पालक पत्तों से हरा रंग निकाला जाता है,जिसे मक्के के सूखे डंठल (अरारोट) में मिलाकर शुद्ध और सुरक्षित गुलाल बनाया जाता है। महिलाओं ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी तरह के आजीविका मूलक प्रशिक्षण से अधिक से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। हर्बल गुलाल की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाएं अब बड़े पैमाने पर बनाने की योजना बना रही हैं। जिससे स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका का नया द्वार भी खुलेगा।

क्या यही है 'ज्ञान, गति का संकल्प'?

एनएचएम कर्मचारियों की उपेक्षा पर सवाल

समवेत शिखर संवाददाता

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट का थीम 'ज्ञान के उत्थान, गति की शक्ति से, संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए' रखा गया है।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरि और गरियाबंद जिलाध्यक्ष अमृत राव भोंसले ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा की यह थीम राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में सकारात्मक संदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की विशेष घोषणा या ठोस पहल नहीं की गई। जिला प्रवक्ता और प्रांतीय प्रतिनिधि भूपेंद्र सिन्हा और भूपेश साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले NHM कर्मचारी वर्षों से सीमित वेतन,अनिश्चित भविष्य और अस्थिर सेवा शर्तों के बावजूद पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। कोविड काल सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों के समय इन कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद बजट में इनके हितों की अनदेखी कई सवाल खड़े करती है। कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोधर महतो और शेखर धुर्वे ने कहा कि विशेष रूप से यह भी स्मरणीय है कि नरेंद्र मोदी के नाम से जारी 'मोदी की गारंटी' में संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का स्पष्ट संकल्प व्यक्त किया गया था। ऐसे में NHM कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि इस बजट में उनके नियमितीकरण, वेतन संरचना में सुधार या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ठोस निर्णय सामने आएंगे।

NHM कर्मचारी संघ का मानना है कि यदि राज्य सरकार वास्तव में ज्ञान के उत्थान और गति की शक्ति के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेती है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने वाले इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता में होना चाहिए। राज्य सरकार से आग्रह करते हैं किःNHM संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में ठोस नीति बनाई जाए।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा 19 सितम्बर 2025 को किये गए घोषणा की 3 माह के भीतर चिकित्सा बीमा, ग्रेड पे, एच आर पालिसी में सुधार, अनुकम्पा नियुक्ति एवं अन्य मांगो को समयबद्ध पूर्ण करने एवं 17500 कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सेवा स्थिरता प्रदान की जाए।

अंततः प्रश्न यही है –क्या यही है 'ज्ञान के उत्थान और गति की शक्ति का संकल्प', जब स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वाले कर्मचारियों की ही अनदेखी की जाए?

भाटापारा के लिए निराशाजनक रहा बजट : विधायक साव

समवेत शिखर संवाददाता

भाटापारा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट से क्षेत्र के लोगों में ना केवल निराशा है बल्कि हर वर्ग के लोगों को हतोत्साहित करने वाला नीरस बजट है,उक्त बाते कांग्रेस विधायक इन्द्र साव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही।

विधायक इन्द्र साव ने अपनी बजट प्रतिक्रिया में कहा कि प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री द्वारा अपने लगातार तीसरे बजट से यह उम्मीद थी कि ऐसा बजट पेश करेंगे की प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा परन्तु बजट से निराशा हुई । यह बजट कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषकों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बजट में रोजगार की कोई बात नहीं कही गई। यहाँ तक की महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित महिलाओं को फिर इस बार निराश किया गया इस योजना से वंचित महिलाओं के नाम को पुनः जोड़ने जैसी घोषणा नहीं हुई। विधायक साव ने कहा कि इस बजट में भाटापारा

विधान सभा क्षेत्र के विकास और उसे सजाने संवारने के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा ना होना क्षेत्र की जनता के हितों की अनदेखी है। क्षेत्र के छात्रों को भी इस बार फिर निराशा हाथ लगी ह उनकी उम्मीदों और उनके सपनों को इस बजट ने ना केवल निराश किया बल्कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और पीछे धकेल कर अन्य नगरों कस्बों की ओर जाने बाध्य कर दिया। 57 हजार शिक्षकों के रिक्त पदो के लिए बजट में मात्र 5 हजार भर्ती का उल्लेख ऊँट के मुँह में जीरा के समान है ' अवैध शराब एवं अन्य नशीली पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रावधान नही किया गया है। इस बजट में भी लोक सेवकों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई बात नही की गई है। विधायक साव ने कहा कि सरकारी दफ्तरों को चलाने के लिए स्थापना बजट का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है,जिससे सरकार की कथनी और करनी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बने उप जेल के लिए जेल कालोनी बनाए जाने,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय और अपर कलेक्टर कार्यालय चलाने के लिए अब तक स्टाफभी स्वीकृत नहीं किया गया और ना ही स्थापना व्यय राशि का प्रावधान किया गया है। डबल इंजन की सरकार का ढोंग आज क्षेत्र की जनता को दिख गया और समझ आ गया कि भाजपा की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि भाटापारा का विकास करना नहीं चाहते। विधायक इंद्र साव ने कहा कि चिकित्सा सेवा में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह बजट बेमानी वाला साबित हुआ। मेडिकल की पढ़ाई करने मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग यहां अनवरत छात्र गण और उनके परिजन कर रहे है लेकिन इस बार फिर मेडिकल कॉलेज की घोषणा ना होने से छात्रों को मायूस होना पड़ा है।

महानदी की छाती पर चल रहा चैन माउंटेन का कहर, सैकड़ों हाइवा से रोज रेत पार, जिम्मेदार मौन!

समवेत शिखर संवाददाता

नवापारा-राजिम। ग्राम दुलना में महानदी इन दिनों रेत माफ़ियाओं के निशाने पर है। महीनों से दिन-दहाड़े और रात के अंधेरे में अवैध रेत उत्खनन का खेल बेखौफजारी है। प्रतिदिन सैकड़ों हाइवा ट्रिप भरकर रेत का परिवहन किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फखानापूर्ति नजर आ रही है। नदी के बीचों-बीच भारी मशीनें उतारकर गहराई तक खुदाई की जा रही है, जिससे महानदी की धारा और प्राकृतिक संरचना बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जिस स्थान पर अवैध उत्खनन हो रहा है, वहां से कुछ ही दूरी पर बना एनीकेट खतरे की जद में है। अगर इसी तरह अंधाधुंध खनन जारी रहा तो एनीकेट की नींव कमजोर पड़ सकती है और बड़ी तकनीकी क्षति या हादसा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि बिना विभागीय संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर रोजाना सैकड़ों गाड़ियों का संचालन संभव नहीं। सवाल उठ रहा है कि आखिर खनिज विभाग, राजस्व अमला और प्रशासन की निगरानी कहां है? महानदी का सीना छलनी हो रहा है, शासन को करोड़ों के राजस्व की चपत लग रही है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है – लेकिन जिम्मेदार विभाग अब भी कटघरे में खड़ा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस खुली लूट पर कब तक चुप्पी साधे रहता है और कब रेत माफ़ियाओं पर सख्त कार्रवाई होती है।

अंडरब्रिज के पास ऊंचा स्पीड ब्रेकर बना परेशानी का कारण

नागरिकों ने की सुधार की मांग

समवेत शिखर संवाददाता

नवापारा-राजिम। सोनेसिली-कुर्रा मार्ग पर रेलवे द्वारा अंडरब्रिज के समीप बनाया गया स्पीड ब्रेकर इन दिनों आम नागरिकों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्रेकर की ऊंचाई आवश्यकता से अधिक रख दी गई है, जिससे छोटे चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

वाहन चालकों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर इतना ऊंचा है कि कई वाहनों के नीचे का इंजन और चेसिस ब्रेकर से टकरा रहे हैं। इससे वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी

हुई है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। विशेषकर रात के समय और आपात स्थिति में यह स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती है।

ग्रामीणों और नियमित रूप से इस मार्ग से गुजरने वाले नागरिकों ने रेलवे के संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई को मानक अनुरूप किया जाए, ताकि आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके। लोगों का कहना है कि सुरक्षा के उद्देश्य से स्पीड ब्रेकर बनाना उचित है, लेकिन उसकी ऊंचाई ऐसी न हो जिससे आमजन को परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़े।

नागरिकों ने शीघ्र समाधान की अपेक्षा करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे।

संत गाडगे जयंती समारोह में शिवरतन शर्मा शामिल हुए

समवेत शिखर संवाददाता

भाटापारा। झेरिया धोबी समाज तरेंगाराज के द्वारा रामजानकी मंदिर प्रांगण मावली सिंगारपुर में राष्ट्र संत शिरोमणि संत गाडगे बाबा का जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उक्त अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा द्वारा संत गाडगे बाबा की तस्वीर में माल्यार्पण कर दीप प्रवज्जलित किया। रजक समाज तरेंगाराज के अध्यक्ष त्रिलोचन रजक द्वारा मुख्य अतिथि शिवरतन शर्मा का पुष्पहार से स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि शिवरतन शर्मा के द्वारा संत

गाडगे बाबा जी महाराज के द्वारा समाज देश में उनके द्वारा किए गये स्वच्छता पर प्रकाश डाला गया उन्होंने कहा समाज में जेदभाव, छुआछूत नहीं बल्कि स्वच्छता को अपनाकर स्वीकार करना चाहिए। उक्त अवसर पर गन्नू लाल रजक , कनक मनहरे ,खुमान वर्मा ,त्रिलोचन रजक, लाला राम रजक, परशु राम रजक नारायण निर्मलकर, ईश्वर रजक, प्यारे लाल रजक , रतन निर्मलकर , हरि राम रजक, मनोज निर्मलकर ,जवाहर लाल रजक, भगत राम रजक, जीवन लाल निर्मलकर, चित्रकांत रजक, नरेश रजक, उदे राम रजक, कमल रजक ,भारत ,भूषण रजक, भगवती रजक, फगू राम रजक, इतवारी रजक, गंगा राम रजक ,रेवा राम रजक, मन्नू राम रजक, जयराम रजक, सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

सुत सारथी समाज ने सुमंत जयंती पर किया पत्रकारों का सम्मान

वार्षिक सामाजिक सम्मेलन में सुत सारथी कल्याण बोर्ड गठन की उठी मांग

समवेत शिखर संवाददाता

कुरूद। सुत सारथी समाज जिला धमतरी द्वारा सुमंत जयंती एवं वार्षिक सामाजिक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज की एकजुटता प्रदर्शित करते हुए शासन से सुत सारथी समाज कल्याण बोर्ड के गठन की प्रमुखता से मांग की गई। रविवार को कुरूद स्थित छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम का आगाज अतिथियों एवं सामाजिक पदाधिकारियों द्वारा सुमंत सारथी एवं सुत जी महाराज के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर और पूजा-अर्चना के साथ किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रेस क्लब कुरूद के संरक्षक कृपाराम यादव, महासचिव धनसिंग सेन, रवि शर्मा, श्रवण साहू और दीपक साहू शामिल हुए।स्वागत भाषण देते हुए जिला अध्यक्ष केशव बंछोर ने कहा कि जिला धमतरी में हमारा समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ संगठित हो रहे हैं। उन्होंने समाज की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि छोटे समाज को अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार ऐसे

आयोजनों की आवश्यकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के संरक्षक कृपाराम यादव ने कहा कि सारथी समाज भले ही संख्या बल में यह समाज कम नजर आता हो, लेकिन आपकी संगठित शक्ति और अपनी परंपराओं के प्रति समर्पण आपको एक विशिष्ट पहचान देता है। आज के दौर में जब आधुनिकता हावी है, तब भी आप अपनी जड़ों और पूर्वजों के आदर्शों को सहेज कर रखे हुए हैं, यह सराहनीय है।महासचिव धनसिंग सेन ने कहा कि कोई भी समाज छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी सोच और गतिविधियां उसे बड़ा बनाती हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रेस क्लब समाज की मांगों को शासन तक पहुंचाने में सेतु का कार्य करेगा। वहीं श्रवण साहू ने कहा कि सुत सारथी समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और सेवाभावी रहा है।उन्होंने कहा कि सिर्फ भीड़ को समाज नहीं कहते, बल्कि एकता और गौरवशाली इतिहास को संजोए रखना ही समाज का असली अस्तित्व है।सम्मेलन में समाज के प्रतिभावान बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा। अतिथियों को समाज की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला सचिव मनीष सारथी, कोषाध्यक्ष रेखराम सारथी, सनातन नाग, दुखित सारथी, कृष्णा सारथी, भुपेंद्र सारथी, सोमनाथ सारथी, गोपाल सारथी, घनश्याम सारथी, सुरेश, विकास, रतन, रवि और ललित सारथी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु और मातृशक्ति उपस्थित रहे।

आर्थिक स्थिति कमजोर, विलुप्ति की कगार पर पारंपरिक व्यवसाय-सम्मेलन के दौरान जिलाध्यक्ष केशव राम बंछोर एवं पदाधिकारियों ने अतिथियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों और विकासखंडों में समाज की लगभग 5 लाख आबादी निवासरत है। इस समाज का मुख्य व्यवसाय वैदिक काल से ही घोड़ा-गाड़ी और रथ चलाना रहा है। आज भी विभिन्न समाजों के वैवाहिक कार्यक्रमों में घोड़ी चढ़ाई या रथ का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन विडंबना यह है कि इस कार्य में महारत रखने वाला सुत सारथी समाज आज आर्थिक तंगी के कारण इस व्यवसाय से दूर होता जा रहा है।आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण समाज के बहुत कम लोग ही अब घोड़ा-घोड़ी पालने या रथ रखने में सक्षम हैं।समाज का यह कार्य वर्तमान में विलुप्त होने की स्थिति में है। जिसको शासन के द्वारा संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है।उन्होंने समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने और इस पारंपरिक धरोहर के संरक्षण हेतु सुत सारथी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की। जिला सचिव मनीष सारथी ने भी समाजजनों को संबोधित करते हुए शिक्षा, दीक्षा के साथ नशामुक्त समाज की निर्माण में अहम भूमिका निभाने की बात कही।

'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म पर तत्काल रोक लगाने की मांग : रमेश यदु

समवेत शिखर संवाददाता

भाटापारा। सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय की अति आवश्यक व जिसमें 27 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विरोध के लिए सर्व सम्मति के चर्चा करते हुए इसे यादव समाज के स्वाभिमान के विरुद्ध सोची समझी साजिश बताया गया। वहीं सामाजिक भावनाओं को आहत करने का कुत्सित प्रयास मानते हुए इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग हेतु प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया।

सर्वसम्मति से 25 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री व फिल्म बोर्ड के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक को संबोधित करते हुए सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु ने इसे समाज को बदनाम करने का सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि समाज के स्वाभिमान के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने 25 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया, वहीं युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर यादव ने युवाओं को विरोध प्रदर्शन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही, अपने उद्बोधन में महिला प्रदेश अध्यक्ष धनमती यादव ने समाज के बहन बेटियों को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ महिलाओं को आगे आकर विरोध दर्ज कराने में सहभागिता की बात कही, सभी वक्ताओं ने एकमत से फिल्म को समाज के अस्मिता के खिलाफ मानते हुए बैन लगाने की मांग की है। विदित हो फिल्म निमार्ता के द्वारा 27 फरवरी को यादव जी की लव स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें यादव लड़की को मुस्लिम लड़के के प्रेम कथा को प्रदर्शित किया गया है, इसे देश भर मे यादव समाज द्वारा सामाजिक भावनाओं को आहत करने तथा सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना मानकर फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। यादव समाज के रमेश यदु , डीसी यादव , धनमती यादव , परमेश्वर यादव , देवनारायण यादव सहित सैकड़ो यादव के नाम व हस्ताक्षर उल्लेखित है।

►► न्यूज ब्रीफ

वित्त मंत्री चौधरी ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा

रायपुर। बजट 2026/2027 में वित्त मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा पेश किया बजट हर वर्ग का ध्यान रखा गया। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के टाप पांच राज्यों में रहेगा। बहुत ही सराहनीय बजट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सिंधी काउंसिल ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष ललित जैसिंग एवं महासचिव सुनील कुकरेजा उपाध्याय धनेश मटलानी रितेश वाधवा ने बधाई एवम शुभकामनाएं दी। उक्त अवसर पर एन डी गजवानी जीतू लोहाना सोमवंशी जी उपस्थित थे।

बजट विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी : बजाज

नवापारा राजिम। जिला पंचायत रायपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अशोक बजाज ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा

प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने वाला है तथा इसमें किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। अशोक बजाज ने कहा कि बजट में अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने विशेष रूप से किसानों के लिए की गई घोषणाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने वाले प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नई दिशा देने वाला है और आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता है। श्री बजाज ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

'संकल्प' थीम पर आधारित वर्ष 2026 का बजट छग के विकास का दृढ़ आधार : साहू

फिंगेश्वर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 - 27 का बजट, जिसकी थीम ÷संकल्प÷ है, प्रदेश के सर्वांगीण

विकास के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह विचार भारतीय जनता पार्टी के राजिम मंडल अध्यक्ष रिकेश साहू ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ÷संकल्प÷ केवल एक थीम नहीं, बल्कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्पष्ट संकल्प है। यह बजट किसानों की आय वृद्धि, युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। श्री साहू ने कहा कि बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांव, गरीब और किसान को सीधा लाभ मिलेगा। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और विकास की नई दिशा तय करेगा, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ÷संकल्प÷ थीम पर आधारित यह बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और छत्तीसगढ़ को प्रगति के नए आयामों तक पहुंचाएगा इस सराहनीय और जनकल्याण बजट के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया है।

कृषि और शिक्षा को मजबूती देने वाला ऐतिहासिक बजट : मेघवानी

नवापारा राजिम। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट को कृषि, किसान और युवा हितैषी बताते हुए भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अंकित मेघवानी ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्तमंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अंकित

मेघवानी ने कहा कि प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान कर सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को संबल देने का कार्य किया है। वहीं कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया की शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रावधानों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं के करियर काउंसलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान भविष्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही नालंदा लाइब्रेरी को करियर एवं उद्यमिता मार्गदर्शन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बेहतर वातावरण और संसाधन उपलब्ध होंगे। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अंकित मेघवानी ने कहा कि यह बजट किसान, मजदूर, युवा और आम नागरिकों के सपनों को साकार करने वाला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और प्रस्तुत बजट से छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

नालंदा परिसर के लिए 4.50 करोड़, भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग के लिए 25 करोड़ तथा मॉडल उप पंजीयक कार्यालय की स्वीकृति मिली

समवेत शिखर संवाददाता

भाटापारा। छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्तुत बजट में भाटापारा क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों की बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। जनप्रिय नेता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा के सतत प्रयासों और प्रभावी पहल के फलस्वरूप भाटापारा नगर को 4 करोड़ 50 लाख की लागत से नालंदा परिसर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह स्वीकृति नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव की पूर्व घोषणा में शामिल था। इसके अतिरिक्त भाटापारा - बलौदाबाजार 24 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़ की राशि स्वीकृति

बजट में दी गई है जिससे उक्त दोनो शहरों के बीच आवागमन सुगम व सहज रूप से हो सकेगा। इससे क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। साथ ही भाटापारा में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे नागरिकों को रजिस्ट्री एवं उससे संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध होंगी। नालंदा परिसर के निर्माण से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं एवं अध्ययनशील वातावरण की आवश्यकता रखने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक, शांत एवं संसाधनयुक्त अध्ययन केंद्र मिलेगा। उक्त बजट घोषणा से भाटापारा को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी । छत्तीसगढ़ के मौजुदा बजट में भाटापारा को दिये गये विभिन्न सौगात पर शिवरतन शर्मा ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा है कि भाटापारा के विकास के लिए हमारा संकल्प निरंतर जारी है। इसी कड़ी में नालंदा परिसर युवाओं के सपनों को साकार करने का केंद्र बनेगा वहीं भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग क्षेत्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा मॉडल उप पंजीयक कार्यालय से आम नागरिकों को सुगम और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। यह सब प्रदेश नेतृत्व के सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग का परिणाम है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय , उपमुख्यमंत्री अरूण साव व वित्त मंत्री ओ पी चौधरी व क्षेत्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया है । इधर नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ बजट 2026 में मिली ये विकास की सौगातें भाटापारा के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। शिक्षा, अधोसंरचना और प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में यह निर्णय नगर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

भोपाल से धनबाद और चोपन के लिए दो नई ट्रेनें, सीएम यादव ने दिखाई हरी झंडी प्रदेश

भोपाल। भोपाल से झारखंड और पूर्वी उत्तरप्रदेश के लिए बहुप्रतीक्षित रेल सेवा मंगलवार शाम शुरू हो गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन से भोपाल-धनबाद और भोपाल-चोपन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम में भोपाल के सांसद (आलोक शर्मा), डॉ. राजेश मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंगरौली-सीधी क्षेत्र लंबे समय तक रेल संपर्क के मामले में पिछड़ा रहा, जबकि यह ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध इलाका है। अब नई ट्रेन सेवा से यहां के लोगों को नियमित आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास का नया मार्ग है। मध्यप्रदेश, झारखंड और पूर्वी भारत के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

अनियमित, संविदा कर्मी फिर ठगे गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, रोजगार सरकार की प्राथमिकता में नहीं : रूपेश

केवल कॉर्पोरेट मुनाफा और संसाधनों के लूट के संकल्प का बजट : टिकेश

समवेत शिखर संवाददाता

फिंगेश्वर। साय सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में आयरन स्टील, रोलिंग मिल, कृषि और वनोपज प्रसंस्करण आधारित इकाइयां ही औद्योगित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन इस बजट में उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं है। बस्तर की इमली के मांग दुनियां भर में थी, जगदलपुर का मंडी एशिया की सबसे बड़ी इमली

मंडी हुआ करती थी, इस सरकार ने उसे पूरा खत्म कर दिया। उद्योग के नाम पर केवल वनों की कटाई और खनिज संसाधनों के असंतुलित दोहन को ही प्रोत्साहन मिल रहा है, ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी टिकेश साहू ने कहा है कि भाजपा की सरकार में किसानों के साथ फिर से धोखा किया है। पिछले 2 साल की तरह इस साल भी एमएसपी वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं दिया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन एमएसपी वृद्धि का लाभ देते हुए 2660 रुपए में खरीदी किया, इस बजट से साफ है कि भाजपा सरकार एमएसपी वृद्धि का लाभ किसानों को आने वाले साल में भी नहीं देगी।

हर वर्ग के सपनों को साकार करने वाला जनहितैषी बजट : शीला सिन्हा

विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में मजबूत और निर्णायक कदम

समवेत शिखर संवाददाता

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट को जिला पंचायत सभापति श्रीमती शीला टाकेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप है जो गांव से लेकर शहर तक समान रूप से प्रगति की नई राह प्रशस्त करेगा।

श्रीमती सिन्हा ने कहा कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग किसान, युवा, महिला, मजदूर, व्यापारी और मध्यमवर्ग की आवश्यकताओं का गंभीरता से ध्यान रखा गया है। सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव तक उसकी रोशनी पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य सरकार समावेशी विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। बजट में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रावधान किसानों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि

लाएंगे। सिंचाई, समर्थन मूल्य, भंडारण और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे कदम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होगा। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने वाले प्रावधान राज्य को नई ऊर्जा देंगे। नई औद्योगिक संभावनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे जिससे प्रदेश की प्रगति को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में किए गए प्रावधान सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाते हैं। स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा, मातृत्व लाभ योजनाएं और सुरक्षा से जुड़े कदम महिलाओं को आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे।स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना पर बढ़ाया गया निवेश छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयाम देगा। बेहतर अस्पताल, आधुनिक स्कूल, सड़कों और पुलों का विस्तार प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। अंत में श्रीमती शीला टाकेश सिन्हा ने कहा कि यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की ओर एक मजबूत और निर्णायक कदम है। यह बजट प्रदेशवासियों के सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनभागीदारी और पारदर्शिता के साथ यह बजट राज्य को प्रगति और समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गोंदिया-जबलपुर दोहरी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति

5,236 करोड़ की लागत से 231 किलोमीटर रेलखंड का दोहरीकरण, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति

समवेत शिखर न्यूज

रायपुर/बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की गोंदियाङ्कजबलपुर दोहरी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है । इस परियोजना की अनुमानित लागत ?5,236 करोड़ है तथा इसे 5 वर्षों की अवधि में पूर्ण किया जाएगा ।

गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण परियोजना गोंदिया पर हावड़ा-मुंबई उच्च घनत्व रेल मार्ग तथा जबलपुर पर इटारसीङ्कवाराणसी उच्च उपयोगिता रेल मार्ग को जोड़ती है । यह प्रयागराज एवं वाराणसी से चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की ओर सबसे छोटा रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी, जिससे उत्तरङ्कदक्षिण रेल संपर्क को सुदृढ़ता मिलेगी ।

परियोजना का विवरण एवं प्रमुख विशेषताएँ- रेलखंड लंबाई: 231 किलोमीटर- जिले: गोंदिया (महाराष्ट्र), जबलपुर, मंडला, सिवनी एवं बालाघाट (मध्य प्रदेश)

वन्यजीव संरक्षण: वन्यजीव अंडरपास एवं फेंसिंग के लिए 450 करोड़ का प्रावधान, परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ-यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन में वृद्धि तथा रेल क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार, प्रमुख तीर्थ स्थलों–अयोध्या धाम, वाराणसी, प्रयागराज, रामेश्वरम, मदुरै आदि–के लिए बेहतर एवं सुगम रेल संपर्क, प्रमुख पर्यटन स्थलों–कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिज़र्व, कचनार शिव मंदिर, गांगुलपारा बाँध, धुआंधार जलप्रपात आदि–तक आसान आवागमन, विद्युत संयंत्रों, आयुध निर्माणी, खनन क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को बेहतर रेल सुविधा, अतिरिक्त माल परिवहन क्षमता: 7.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष, पर्यावरणीय लाभ: प्रति वर्ष लगभग 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, जो लगभग 63 लाख वृक्षारोपण के समतुल्य है, परिवहन लागत में बचत: लगभग ?350 करोड़ प्रतिवर्ष

रोज़गार सृजन: लगभग 78 लाख मानव-दिवस-प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत नियोजित यह परियोजना एकीकृत योजना एवं बहुआयामी संपर्क को सुदृढ़ करेगी । गोंदियाङ्कजबलपुर दोहरी रेल लाइन परियोजना से न केवल रेल परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिकङ्कआर्थिक विकास, रोज़गार के अवसरों और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी नई गति मिलेगी ।

Uniglobe.
Star India Travel

STAR ELITE LUXURY REDEFINED

PREFERRED HOTEL PARTNER

TAJ · ANANTARA HOTELS·RESORTS·SPAS · LHW · RF · WORLD OF HYATT. · ACCOR · FOUR SEASONS · MANDARIN ORIENTAL THE HOTEL GROUP · ROSEWOOD HOTELS & RESORTS

Vision

ELEVATED PERSONAL SERVICE
Depend on us for peace of mind

UNRIVALED SME TRAVEL EXPERTS
We get you

LOCAL OWNERSHIP & GLOBAL RELEVANCE
You'll feel at home wherever

Purpose: To drive client Success through better travel
Essence: Travel Well
Differentiator: We see Possibilities other can't

T : + 917714070803
M : + 919893146333
M : + 9199301709211
E : mbansal@uniglobestar.in
E : pbansal@uniglobestar.in

A 602-604, 6th Floor, Babylon Tower, VIP Square, Raipur, CHHATTISGARH-492001

Uniglobestar.in

5 करोड़ का गांजा जब्त, कंटेनर भी जब्त

» 9 क्विंटल से ज्यादा मादक पदार्थ पकड़ा गया
» गुप्त चैंबर बनाकर गांजा तस्करी कर रहा था

समवेत शिखर संवाददाता

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपये कीमत का गांजा जब्त किया है।

थाना चिल्फी थाना पुलिस ने नागालैंड पासिंग कंटेनर को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये बताई जा रही है। इसी कंटेनर में गांजा भरकर ले जाया जा रहा था।

वाहन में 30-30 किलो की 30 बोरियों में भरा करीब 9 क्विंटल (900 किलो) गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी आयाज खान, निवासी भरतपुर, राजस्थान को गिरफ्तार किया है। आरोपी यह गांजा ओडिशा से राजस्थान ले जा रहा था।

पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई को जिले में नशे के कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक देवीचंद श्रीश्रीमाल द्वारा समवेत शिखर प्रेस, रजबंधा मैदान, रायपुर से मुद्रित कर प्रकाशित। संपादक : देवीचंद श्रीश्रीमाल, प्रबंध संपादक : विवेक श्रीश्रीमाल, समाचार संपादक: शंकर चंद्राकर*
(* पीआरबी एक्ट के तहत संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार) आर.एन.आई. रजि. क्र.- 52151/91, पो. रजि. नं.-सीजी/आरवाईपी डी.एन./ 28/2023-25 फोन : 0771-4334967, Email : news@samvetshikhar.com, www.samvetshikhar.com

न्यूज ब्रीफ

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद दंतेवाड़ा मे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

बचेली/दंतेवाड़ा। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा मे सीपीआई पार्टी हमेशा ही जल, जंगल, जमीन को लेकर शासन-प्रशासन के आमने-सामने लड़ाई लड़ अपनी अधिकार के लिए सुर्खियों में रहा है। एक बार फिर मुख्य आठ मुद्दे को लेकर स्थान दुर्गा मण्डप दंतेवाड़ा (छ.ग.) में 24 फरवरी 2026 समय - दोपहर 12 बजे से एक दिवसीय धरना करने का निर्णय लिया गया है। अन्य मुद्दे :- बस्तर संभाग के सभी जिलों में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए स्थानीय युवाओं को रोज़गार मुहैया कराया जाए, दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी समेत सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को भर्ती किया जाए जिससे कि बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके, जिले में लचर स्वास्थ्य सेवाएं को सुदृढ़ किया जाए, जिले से मजदूरी के लिए अंतरराज्यों में पलायन को तत्काल रोका जय एवं स्थानीय स्तर पर रोज़गार मुहैया कराई जाए, तेंदू पत्ता का दर 5 रु से बढ़ाकर 8रु किया जाए और तेंदुपत्ता संग्राहकों को नग़द भुक्तान किया जाए, संपूर्ण बस्तर संभाग संविधान की पांचवीं अनुसूची का क्षेत्र है जहां पेशा-ष्ट्ज्ञ. लागू है, जिसका प्रभावी ढंग से पालन कराई जाए और ग्राम सभा को महत्व दिया जाए, किसी भी सर्वे के नाम से अंदरुनी क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासियों को परेशान करना तत्काल बंद कराई जाए, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बोधघाट परियोजना और पोलावरम बांध से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रभावित होने वाले बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए इसपर तत्काल रोक लगाई जाए।

धुड़मारास में धुरवा नृत्य और सिहाड़ी-महुए की माला के साथ हुआ विदेशी विशेषज्ञ का आत्मीय अभिनंदन

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव के प्रतीक बस्तर जिले में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की एक नई इबारत लिखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग की संस्थापक सुश्री किर्सी ह्यवैरिनेन के छह दिवसीय प्रवास का दूसरा दिन बस्तर की अनूठी परंपराओं और आत्मीय आतिथ्य के नाम रहा। सुश्री किर्सी का कारवां मंगलवार को ग्राम धुड़मारास की सुंदर वादियों में पहुँचा, जहाँ धुरवा डेरा होमस्टे में उनका स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं था। धुड़मारास की धरती पर कदम रखते ही सुश्री किर्सी का अभिनंदन स्थानीय परंपरा के अनुसार सिहाड़ी और महुए की विशेष माला पहनाकर किया गया। इस दौरान बस्तर की लोक संस्कृति की जीवंत झलक तब देखने को मिली, जब स्थानीय ग्रामीणों ने धुरवा नृत्य की थाप और पारंपरिक स्वागत गीतों के साथ उनकी अगवानी की। आत्मीयता के साथ किए गए इस स्वागत से सुश्री किर्सी अभिभूत नजर आई और कहा कि उन्हें अपने जीवन में इस तरह की अनुभूति पहली बार हो रही है। आत्मीय स्वागत के पश्चात सुश्री किर्सी ने बस्तर के पारंपरिक खान-पान का लुत्फ उठाया, जहाँ दोपहर के भोजन में उन्हें पूरी तरह स्थानीय और जैविक व्यंजनों से सजी थाली परोसी गई। बस्तर के जायके का अनुभव करते हुए उन्होंने कलम भाजी, सेमी की सब्जी, बोदई की सब्जी और केले की सब्जी जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया।

दिव्यांग एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करना सुनिश्चित करें : कलेक्टर नम्रता जैन

नियद नेल्लानार योजनांतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने के निर्देश

समवेत शिखर संवाददाता

नारायणपुर। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर नम्रता जैन की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने तथा प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के निर्माण एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। उन्होंने दिव्यांग एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने एवं नियद नेल्लानार योजनांतर्गत आने वाले सभी ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने के निर्देश दिये।

बैठक में ग्राम पंचायत हांदावाड़ा के हितामपारा में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, शौचालय, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत नेलवाड़ के आश्रित ग्राम लालसुहनार, आदेर के आश्रित ग्राम चालचेर तथा हितापारा ओरछामेटा में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा हुई। ग्राम धौड़ाई में शिक्षक आवास की सुविधा, ग्राम पंचायत कोशलनार की विभिन्न समस्याओं तथा अलग-अलग मदों के अंतर्गत प्री-फैब्रिकेशन कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने जल शक्ति अभियान कैच द रन के तहत पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों, वन भूमि पट्टा प्रकरणों, नक्सल पीड़ित परिवारों को अनुकम्पा नियुक्ति, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता की भी समीक्षा की। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की समस्याओं, जनमन प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति, शालाओं में शिक्षकों की लापरवाही, विभिन्न ग्रामों में आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक शाला प्रारंभ करने, नल-जल योजनाओं के अपूर्ण कार्य, हैंडपंप एवं बोर खनन तथा सोलर टंकी निर्माण कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने किसानों एवं विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि कार्य के लिए किसानों को शीघ्र बिजली पोल उपलब्ध कराने तथा क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को तत्काल हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर ने ग्राम मसपुर में लंबित विद्युत कनेक्शन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को समय पर कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता प्रशासन की प्राथमिकता है। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों में आधार सुधार शिविर आयोजित कर छात्रों की अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विद्यार्थी का शैक्षणिक कार्य दस्तावेजों के अभाव में प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए व्यापक अभियान चलाने और अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, एसडीएम अभयजीत मण्डावी, डॉ. सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर डीके कोशले, सौरभ दीवान, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. राजेन्द्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार पटेल, सीएमएचओ डॉ. टीआर कुंवर, नगरपालिका सीएमओ आशीष कोर्राम, जनपद सीईओ ओरछा लोकेश चतुर्वेदी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बस्तर की लाइफ लाइन से लेकर पर्यटन तक, विकास की नई इबारत

समवेत शिखर संवाददाता

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के विकास की नई दिशा तय करने वाला साबित हो रहा है। इस बजट के प्रावधानों ने न केवल राजधानी बल्कि बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों के निवासियों और व्यवसायियों में भारी उत्साह भर दिया है। बजट की बारीकियों पर गौर करें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने अधोसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए आम जनजीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की है।

व्यवसायी श्री अनिल लुंकड़ ने इस वित्तीय योजना का पुरजोर स्वागत करते हुए इसे बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उनके अनुसार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रावधान इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगे, वहीं पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा देने की नीति स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करेगी। यह निवेश न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करेगा।

इसी क्रम में वित्तीय विशेषज्ञ और चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री योगेंद्र कौशिक ने बजट के दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दस्तावेज शिक्षा के साथ-साथ प्रदेश के अन्नदाताओं और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला है। उनका मानना है कि युवाओं के लिए किए गए विशेष आवंटन और किसानों की समृद्धि पर केंद्रित योजनाएं राज्य की विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। बजट का यह संतुलित दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है।

बस्तर संभाग की बात करें तो व्यवसायी श्री मनीष मूलचंदानी ने आदर्श शहर समृद्धि योजना को जगदलपुर के भविष्य के लिए क्रांतिकारी बताया है।

संकल्प से सिद्धि को समर्पित बजट : किरण देव

समवेत शिखर संवाददाता

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, दूरदर्शी और राज्य को समृद्ध बनाने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज बताया है। श्री देव ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। बजट राज्य की नीति को प्रदर्शन में, निवेश को परिणामों में और आकांक्षाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' को पूरा करने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक 'विकसित राज्य' बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने बजट को 'ज्ञान' और 'गति का संगम' और 'विकसित छत्तीसगढ़' का आधारस्तम्भ बताते हुए कहा कि बजट में कृषक उन्नति योजना और सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया प्रावधान यह सिद्ध करता है कि हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बिना किसी नए कर के राजस्व बढ़ाना और किसानों को समय पर इनपुट सब्सिडी देना प्रशंसनीय है। बजट में युवाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर जोर दिया गया है। 'अटल निर्माण वर्ष' के तहत बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 'महतारी वंदन योजना' के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ महिलाओं के स्वरोजगार और लखपति दीदी योजना को नई गति देना महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बजट में सड़क, बिजली और ग्रामीण विकास (गति) के लिए आवंटित भारी भरकम राशि से राज्य के सुदूर वनांचलों तक विकास की किरण पहुँचेगी। श्री देव ने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किए गए विशेष प्रावधानों हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह हर छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान और समृद्धि का रोडमैप है।

गांजा बिक्री करने के लिए परिवहन कर रहे दो आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार

समवेत शिखर संवाददाता

जगदलपुर । पुलिस अधीक्षक, श्री शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे के सौदागरों तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य मे प्रतिबंधित अवैध गांजा बिक्री करने के लिए परिवहन करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।

ज्ञात हो कि थाना बोधघाट में दिनांक 23.02.2026 को जरिये मुखबीर से रात्रि में सूचना मिली कि उड़ीसा की ओर से एक सिल्वर कलर की इन्नोवा में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं तथा अपनी इन्नोवा गाड़ी के पीछे सीट में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करते हुए सप्लाई करने के लिए जगदलपुर की ओर आ रहे हैं कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में, अति. पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार डी धोत्रे के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में, थाना प्रभारी बोधघाट अन्य थाना स्टाफ के साथ टीम बनाकर सूचना की तस्दीकी तथा कार्यवाही हेतु तत्काल ओडिसा से आने वाली मैन रोड , आड़ावाल, बरगद पेड़ के पास पहुंचकर नाकाबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार उड़ीसा की ओर से आने वाली गाड़ियों को चेक करने लगे जो नाकाबंदी चेकिंग के दौरान मुखबिर के बताए अनुसार एक सिल्वर कलर इन्नोवा गाड़ी आई जिसे रोककर देखने पर दो व्यक्ति सवार मिले जिनसे नाम पता पूछने पर घबराने लगे तथा भागने का प्रयास करने लगे जिन्हें पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम बाल्बो उर्फ़ बल्लब भत्तरा पिता चेतन भत्तरा, उम्र 40 साल, ग्राम मोहरगुड़ा, थाना पापडाहांडी, जिला नबरंगपुर तथा अमरज्योति हिरन पिता अशोक कुमार हिरन, उम्र 44 साल, ग्राम खोलीगुड़ा, थाना दाबूगांव, जिला नबरंगपुर जिनके गाड़ी की एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत तलाशी लेने पर पीछे सीट में भूरे रंग के टेप से लिपटे छोटे बड़े कुल 08 पैकेट्स में कुल 42.431 किग्रा कुल किमती 21,21,550/ रु के अवैध मादक पदार्थ गांजा, एक देशी पिस्टल 02 नाग जिंदा कारतूस बरामद हुआ जिसे अवैध रूप से कब्जे में रखकर परिवहन करते पाए गए।

खेल-व्यापार-मनोरंजन

फुटबॉल स्टार नेमार का संन्यास पर बड़ा बयान वर्ल्डकप 2026 हो सकता है आखिरी टूर्नामेंट

नई दिल्ली। ब्राज़ीलियाई फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में से एक नेमार ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने माना कि 2026 सीजन उनके करियर का आखिरी पड़ाव हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वह फीफा विश्व कप 2026 में ब्राज़ील के लिए एक आखिरी बार मैदान पर उतरना चाहते हैं।

हाल ही में एक इंटरव्यू में 34 वर्षीय नेमार ने कहा कि वह अब साल-दर-साल सोच रहे हैं और दिसंबर 2026 तक पहुंचते-पहुंचते संन्यास लेने का फैसला भी कर सकते हैं। उनके मुताबिक यह साल न केवल क्लब बल्कि राष्ट्रीय टीम के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि विश्व कप का साल है और वह खुद भी इसे खास मानते हैं। गौरतलब है कि नेमार करीब 12 साल बाद अपने बचपन के क्लब सैंटोस लौटे हैं। इससे पहले वह एफसी बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के लिए खेल चुके हैं। फ्रांस में उनका कार्यकाल चोटों से प्रभावित रहा, जबकि सऊदी क्लब अल हिलाल के साथ भी उनका समय लंबा नहीं चला। सैंटोस ने उनका अनुबंध दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है, लेकिन भविष्य को लेकर अटकलें बनी हुई हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 के बाद से लगातार चोटों ने उनके खेल समय को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस दौरान उन्होंने 29 मैच खेले, 11 गोल किए और पांच असिस्ट दिए, लेकिन लगभग 200 दिन मैदान से बाहर भी रहे। घुटने की गंभीर चोट के चलते उन्हें सर्जरी करानी पड़ी, जिससे लय टूट गई।

हालांकि आंकड़े बताते हैं कि वह अब भी ब्राज़ील के सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। 128 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 79 गोल उनके नाम दर्ज हैं, जो राष्ट्रीय टीम में उनकी अहमियत को दर्शाते हैं।

इंग्लैंड टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंची, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप का 5वां सुपर-8 मैच रोमांचक मोड़ पर है। 165 रन का टारगेट चेज कर रही इंग्लैंड को 6 बॉल पर 3 रन की जरूरत है, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स को 2 विकेट गिराने है। 19 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 162/8 है। जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन क्रीज पर हैं। हैरी ब्रूक 100 रन बनाकर आउट हुए।

सैम करन (16 रन) को उस्मान तारिक ने मोहम्मद नवाज के हाथों कैच कराया। उन्होंने टॉम बैंटन (2 रन) को भी आउट किया। शाहीन अफरीदी ने फिल सॉल्ट (जीरो), जोस बटलर (2 रन) और जैकब बेथेल (8 रन) को पावरप्ले में पवेलियन भेज दिया। शाहीन (134 विकेट) टी-20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर बन गए हैं। उन्होंने हारिस रऊफ (133 विकेट) को पीछे छोड़ा।

कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 164 रन बनाए। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 63 रनों की पारी खेली। जबकि बाबर आजम और फखर जमान ने 25-25 रन का योगदान दिया।

इंग्लैंड की ओर से लियाम डॉसन ने 3 विकेट झटके। जोफ्रा आर्चर और जैमी ओवरटन को 2-2 विकेट मिले। आदिल रशीद को एक विकेट मिला। एक बैटर रनआउट हुए। मैच का स्कोरबोर्ड

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

इंग्लैंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जैमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक।

ज्ञान के मंच पर सजी प्रेरणा की महफ़िल: 'कौन बनेगा करोड़पति' में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे नाना पाटेकर

मुंबई। भारत का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर दर्शकों के लिए लेकर आया एक यादगार और प्रेरणादायक विशेष एपिसोड। इस खास अवसर पर मंच की शोभा बढ़ाई दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने, जिनकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को भावनात्मक और अर्थपूर्ण बना दिया। इस खास कड़ी में ज्ञान के साथ-साथ अनुभव और संवेदनाओं का अनूठा संगम देखने को मिला। नाना पाटेकर ने अपने अभिनय सफर, संघर्षों, सामाजिक सरोकारों और जीवन के मूल्यों पर खुलकर विचार साझा किए।

उनकी प्रेरक बातों ने न केवल हॉट सीट पर बैठे प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि दर्शकों को भी सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

एपिसोड की शुरुआत में ही शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने नाना पाटेकर का स्वागत किया। दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच वर्षों पुरानी मित्रता, आपसी सम्मान और सिनेमा से जुड़े अनुभवों की झलक मंच पर साफ दिखाई दी। एक खास पल तब आया जब अमिताभ बच्चन ने नाना पाटेकर की सादगी और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की, जिस पर नाना ने विनम्रता से कहा कि ÷इंसान को जमीन से जुड़ा रहना ही सबसे बड़ी सफलता है।÷ यह संवाद दर्शकों के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। 'कौन बनेगा करोड़पति' केवल एक शो नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनने का अवसर देता है। यह शो वर्षों से ज्ञान, आत्मविश्वास और सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम रहा है। नाना पाटेकर की गरिमामयी उपस्थिति ने इस परंपरा को और भी सशक्त बनाया।

एचडीएफसी बैंक ने गुवाहाटी में नई टेक और डिजिटल फैक्ट्री का शुभारंभ किया

गुवाहाटी। भारत के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने आज गुवाहाटी में अपनी नई टेक और डिजिटल फैक्ट्री का शुभारंभ किया। यह सुविधा असम में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेशन और टैलेंट इनक्यूबेशन के लिए एक सेंटर के तौर पर काम करेगी, जिससे स्टेट में एआई डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी टैलेंट पूल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा बैंक की असम में पहली और देश भर में चौथी है। बैंक की अभी मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम में टेक और डिजिटल फैक्ट्रियां हैं।

इस सुविधा का उद्घाटन असम के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कैज़ाद भरूचा, बैंक के चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर श्री रमेश लक्ष्मीनारायण असम सरकार के गणमान्य लोगों और एचडीएफसी बैंक के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में किया। यह सुविधा राज्य में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को करियर के मौके भी देगी, जिससे वे अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सीधे योगदान दे सकेंगे। बैंक असम और आस-पास के राज्यों से लोकल टेक टैलेंट का फ़ायदा उठाकर टेक और डिजिटल फ़ैक्टरी के लिए अपनी क्षमताओं को मज़बूत करेगा। इसका मकसद एआई, क्लाउड, डेटा और कोर इंजीनियरिंग ट्रैक में कोर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, ताकि स्टेट में डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की क्षमता को खोला जा सके। एचडीएफसी बैंक ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ÷एडवांटेज असम 2.0÷ के हिस्से के तौर पर असम सरकार के साथ पार्टनरशिप की है। इस सांझी पहल के तहत एचडीएफसी बैंक और असम सरकार बीएफएसआई और फिनटेक सेक्टर से जुड़े एक स्ट्रक्चर्ड स्किल-बिल्डिंग करिकुलम के ज़रिए इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ के साथ एकेडमिक नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। कैंपस-टू-कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंसी पर केंद्रित, यह प्रोग्राम बैंकिंग और फिनटेक इंडस्ट्री में नौकरी की ज़रूरतों के हिसाब से है। करिकुलम में ज़रूरी बैंकिंग नॉलेज और नए ज़माने के आईटी डोमेन शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ के छोटे कारोबारियों को मिलेगी आर्थिक रफ्तार : पर्पल फाइनेंस ने भिलाई और राजनांदगांव में खोली नई शाखाएं

भिलाई। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आर्थिक मजबूती देने वाली प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर्पल फाइनेंस ने अब छत्तीसगढ़ में भी अपने कदम रख दिए हैं। राज्य के छोटे कारोबारियों को व्यापार में नई उड़ान देने के मकसद से कंपनी ने भिलाई और राजनांदगांव में अपनी नई शाखाओं का शानदार आगाज किया है।

इस नए विस्तार के साथ ही पर्पल फाइनेंस की अब सात राज्यों में कुल 46 शाखाएं हो गई है, जो पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में कंपनी का एक बड़ा कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों के उन छोटे कारोबारियों तक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लोन पहुंचाना है, जिन्हें आमतौर पर पारंपरिक बैंकों से आसानी से वित्तीय मदद नहीं मिल पाती।

पर्पल फाइनेंस मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, डेयरी व्यवसाय, किराना स्टोर, रिटेल शॉप और छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर प्रॉपर्टी पर लोन की सुविधा दे रहा है। इसके तहत कारोबारियों को पांच लाख से लेकर तीस लाख रुपये तक का सेक्योर्ड बिजनेस लोन दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से ग्राहकों को महज पांच घंटे के भीतर लोन की सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाती है। इससे व्यापारियों के कीमती समय की बचत होती है और वे बिना किसी रुकावट के अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं।

इन नई शाखाओं का उद्घाटन पर्पल फाइनेंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अजय कुमार पांडे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व सीईओ सब्यसाची रथ ने किया। इस मौके पर अजय कुमार पांडे ने बताया कि विदर्भ क्षेत्र और मध्य प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बाद छत्तीसगढ़ आना उनके लिए एक स्वाभाविक कदम था। उन्होंने कहा कि इस राज्य में छोटे उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं, और इस पहल से कारोबारियों को आसानी से लोन मिल सकेगा जिससे वे अपना व्यापार तेजी से बढ़ा सकेंगे।

संकल्प बजट 2026-27 : समावेशी विकास से आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर बड़ा कदम : अंबेश जांगड़े

जांजगीर। छग के वित्त मंत्री ओमप्रकाश चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट की तारीफ करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अंबेश जांगड़े ने कहा कि संकल्प बजट 2026-27 राज्य के सर्वांगीण और संतुलित विकास का रोडमैप है। लगभग 1.72 लाख करोड़ के इस बजट का उद्देश्य केवल वित्तीय प्रावधान करना नहीं, बल्कि नीति से परिणाम तक विकास को जमीन पर उतारना है। यह बजट सामाजिक न्याय, आर्थिक मजबूती और क्षेत्रीय संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है

बजट विकास, उद्योग और जनकल्याण की दिशा में बड़ा कदम : सुल्तानिया

पहले बजट 5700 करोड़ की तुलना में 30 गुना हुई वृद्धि, बजट पंहुचा 1 लाख 72 हजार करोड़

समवेत शिखर संवाददाता

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत लगभग 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये के बजट को विकासोन्मुख और जनहितकारी बताते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जशपुर जिला संगठन प्रभारी अमर सुल्तानिया ने कहा कि यह बजट प्रदेश के भविष्य को मजबूत आधार देने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की दूरदृष्टि से राज्य सरकार ने गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं तैयार की हैं। साथ ही बताया कि करीब 5,700 करोड़ से बढ़कर 1.72 लाख करोड़ तक पहुँचा बजट लगभग 30 गुना वृद्धि के साथ राज्य की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है।

अमर सुल्तानिया ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट में विकास और संवेदनशीलता दोनों का संतुलन दिखाई देता है। प्रदेश में 23 नए उद्योगों के साथ उद्योग पार्क विकसित करने की घोषणा से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य मिल सकेगा।

उन्होंने सिरपुर में रिवर फ्रंट और मेडिटेशन सेंटर बनाने की योजना को सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार इससे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

अमर सुल्तानिया ने बजट में बेटियों के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की सहायता और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण जैसी घोषणाओं को सरकार की संवेदनशील सोच का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ग्रामीण परिवारों और किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का रोडमैप है। सड़क, उद्योग, शिक्षा, कृषि और सामाजिक योजनाओं को एक साथ आगे बढ़ाने की सोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

अंत में सुल्तानिया ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में यह बजट प्रदेश के विकास को नई गति देगा और आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

डॉ. बोधीराम रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित

जांजगीर। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर शिक्षा,साहित्य,समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य व प्रतिभा पर मातृभाषा सेवा के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों का मूल्यांकन कर डॉ.बोधीराम साहू को मातृभाषा रत्न मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित किया गया है । यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा,समाज सेवा की भावना,साहित्य सृजन, कला संस्कृति संवर्धन,शिक्षा प्रदेयो,महनीय शोध कार्य,सुदीर्घ हिंदी सेवा,राष्ट्र परिवार,साहित्य और समाज के प्रति समर्पण,प्रेरक व्यक्तित्व पर प्रदान किया गया है।ज्ञात हो कि ये इसके अलावा राज्य,राष्ट्रीय,अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगभग 309 से भी अधिक सम्मानों से विभूषित हो चुके है।इनके सम्मानित होने पर डा. शिवनारायण देवांगन आस, डा.राघवेंद्र राठौर, बसंत चतुर्वेदी, प्रमोद आदित्य,सत्येंद्र सिंह,विजय प्रधान, जे. सी. साहू,दिलीप साहू, केशव साहू,रामरतन साहू सहित प्रशंसकों ने प्रसन्नता जाहिर की है।

वित्त मंत्री चौधरी का बजट 'विजन' कम और 'डिवीजन' ज्यादा, युवाओं और निकायों के साथ हुआ सौतेला व्यवहार : शर्मा

समवेत शिखर संवाददाता

जांजगीर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट को ÷भ्रम का पुलिंदा÷ बताते हुए स्थानीय पार्षद एवं युवा कांग्रेस नेता प्रिंस चंद्रमौली शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बजट में तकनीक और भविष्य की बात तो की है, लेकिन वर्तमान में बेरोजगारी और बदहाल नगरीय व्यवस्था से जूझ रहे युवाओं व आम जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल 'डिजिटल झुनझुना' मिला है । प्रदेश का युवा सरकारी नौकरियों में नियमित भर्ती और भर्ती कैलेंडर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन सरकार ने उन्हें केवल स्टार्टअप और डिजिटल मिशन के नाम पर उलझा दिया है। बेरोजगारी भत्ता और नई नियुक्तियों पर बजट की चुप्पी चिंताजनक है।

एक निर्वाचित पार्षद के रूप में प्रिंस चंद्रमौली शर्मा ने आपत्ति जताई कि बजट में विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण पर जोर है। स्थानीय वार्डों के विकास के लिए पार्षदों को मिलने वाली राशि और मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जिससे जमीनी स्तर पर विकास कार्य ठप हो जाएंगे।

बजट के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए प्रिंस ने कहा कि सरकार केवल कर्ज लेकर 'घी पीने' का काम कर रही है। बजट का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और गरीब जनता को उम्मीद थी कि इस बजट में वैट (VAT) कम कर पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए जाएंगे, जिससे महंगाई कम होगी, लेकिन वित्त मंत्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।प्रिंस चंद्रमौली शर्मा ने अंत में कहा कि यह बजट केवल कागजों पर 'विकसित छत्तीसगढ़' की बात करता है, जबकि हकीकत में गरीब, युवा और शहर की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। युवा कांग्रेस जल्द ही इस बजट की विसंगतियों को लेकर जनता के बीच जाएगी।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबुती प्रदान करने वाला बजट : अग्रवाल

जांजगीर। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने कल छग सदन मे प्रस्तुत हुए भाजपा सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का संकल्प बजट 2026-27 राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह बजट किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है।

महिलाओं और लड़कियों के विकास आधारित बजट : शर्मा

जांजगीर। भाजपा आईटी सेल जिला संयोजक अनिल शर्मा ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि छग की महतारी व बहनो के लिए इस बजट मे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी योजनाए लाई है जैसे रानी दुर्गावती योजना 18 साल की होने पर लड़कियों को1.5 लाख आर्थिक सहायता मिलेगी। महतारी वंदन योजना के लिए भारी बजट का प्रावधान ?8,200 करोड़ रखा है ताकि विवाहित महिलाओं को आर्थिक मदद मिल सके। आंगनबाड़ी, पोषण कार्यक्रम और महिला विकास के लिए भी खास धनराशि रखी गई है।

स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं का अनिवार्य रूप से कराएं बायोमैट्रिक अपडेट: कलेक्टर

एम. बी. यू अभियान का गांव-गांव में मुनादी कर बच्चों और उनके अभिभावको को करे जागरूक

समवेत शिखर संवाददाता

सक्ती। शासन के निर्देशानुसार एम. बी. यू अभियान (मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट) अन्तर्गत जिले में 5 वर्ष से 16 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने जिले के सभी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का बायोमेट्रिक अपडेट निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।

एम. बी. यू अभियान अन्तर्गत जिले के स्कूलों मे तथा विभिन्न शासकीय कार्यालयो जैसे सभी तहसील कार्यालय, सभी जनपद पंचायत, सभी नगर पंचायत तथा सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालयों में संचालित आधार सेवा केंद्रों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से बच्चों का निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट किया जा रहा है।

कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्कूलों के छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र जारी कर पंचायत सचिवो और रोजगार सहायको के माध्यम से गांव-गांव में मुनादी कर सभी स्कूली छात्र छात्राओं का निर्धारित समय पर अनिवार्य निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट कराए जाने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर ने जमीनी स्तर पर आधार अपडेट की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं शिविर की जानकारी अधिक से अधिक साझा कर सभी बच्चों का अनिवार्य निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट कराए जाने कहा है। कलेक्टर तोपनो ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी 2026 तक जिले के सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा सभी बच्चों के अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का निःशुल्क आधार बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य कराएं, जिससे भविष्य में शासकीय योजनाओं एवं शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।

छात्र-छात्राओं के लिए क्रिकेट का आयोजन किया गया

समवेत शिखर संवाददाता

सक्ती। आईसेक्ट रायगढ़ के एनुअल स्पोर्ट्स में 2026 का आयोजन 21 से 25 फरवरी में किया जा रहा है स्पोर्ट्स मीट के दौरान खेल मैदान पर खिलाड़ियों ने जबरदस्त ऊर्जा का संचार देखने को मिला दिनांक 21 फरवरी को एनुअल स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया गया।

जिसमें प्रथम छात्र एवं छात्राओं हेतु क्रिकेट का आयोजन किया गया छात्र ग्रुप हेतु क्रिकेट में आईसेक्ट आरसीबी विरुद्ध आइसेक्ट मुंबई इंडियंस मैच खेला गया जिसमें आईसेक्ट आरसीबी जीत हासिल की ,छात्रों के ग्रुप में आईसेक्ट महानदी विरुद्ध आईसेक्ट इंद्रावती मैच खेला गया जिसमें इंद्रावती टीम ने जीत हासिल की।

आईसेक्ट संस्थान के लिए खेल गतिविधियों और शारीरिक विकास को शैक्षणिक वातावरण में शामिल करके संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का एक तरीका है इसके उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को नगर स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का ऑप्शन प्रदान करना और समुदाय के भीतर समन्वय को प्लस प्रोत्साहित करना है तीन दिवसीय इस आयोजन में बैडमिंटन, खो खो ,कबड्डी ,निबंध प्रतियोगिता रंगोली प्रतियोगिता ,चित्रकला प्रतियोगिता विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है संस्थान प्रमुख सचिन जैन ने कहा खेल गतिविधियां युवाओं में अनुशासन नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को विकसित करती है।

आपातकालीन सेवा डॉयल-112 ईआरयू में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों सहित वाहन चालकों की ली गई बैठक

महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों मे तत्काल रिस्पांस करने दिए गए दिशा-निर्देश

समवेत शिखर संवाददाता

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी आपातकालीन सेवा डॉयल-112 की योजना को और अधिक प्रभावी बनाने सहित नागरिकों को आपताकालीन स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन मे आज दिनांक को रक्षित केंद्र अंबिकापुर स्थित सभाकक्ष में ईआरयू/ईआरव्ही में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी एवं वाहन चालकों की बैठक ली गई, बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को उनके कर्तव्यों के सम्यक पूर्वक निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया, ईआरयू/ईआरव्ही वाहनों में कर्तव्यस्थ स्टाफको निर्देशित किया गया कि इवेंट के दौरान रिस्पांस टाईम का विशेष ध्यान रखें, इवेन्ट मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर रवाना हो, ईआरयू/ईआरव्ही स्टाप मय वाहन निर्धारित स्टॉपेज पॉइंट पर उपस्थित रहे, ईआरयू/ईआरव्ही में तैनात बल डियूटी के दौरान साफ-सुथरे गणवेश में रहे एवं नशीले पदार्थ का सेवन न करें, ईआरयू/ईआरव्ही का उचित रख-रखाव करें।

बैठक के दौरान नोडल अधिकारी, डॉयल-112 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा ड्यूटी मे तैनात रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों में तत्काल रिस्पांस करने के दिशा-निर्देश दिए एए, साथ ही गंभीर घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौक़े पर रवाना होकर मौक़े के हालत से डीसीसी एवं सी-4 को अवगत कराकर, स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित कर नागरिकों की सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा एवं नोडल अधिकारी द्वारा डॉयल-112 की सेवा मे तैनात जवानों से बात कर ड्यूटी के दौरान आने वाली परेशानियों से रूबरू होकर समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के दिशा-निर्देश डीसीसी प्रभारी को दिए गए, साथ ही अधिकारी/कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को अपनी ड्यूटी सतर्कता पूर्वक करने निर्देशित किया गया, साथ ही आपातकालीन सेवाओं मे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की सख्त समझाईस दी गई।

बैठक के दौरान सरगुजा डीसीसी प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश्वरी चौबे, वाहन शाखा प्रभारी सहायक उप निरीक्षक सत्यनारायण यादव, प्रधान-आरक्षक संजीव कुमार त्रिपाठी, महिला-आरक्षक मनीषा द्विवेदी, आरक्षक अजय कुमार थवाईत, महेंद्र कुमार गोंड, अमन उईके, (GVK) जिला प्रबंधक पुरषोत्तम दास वैष्णव सहित ईआरयू/ईआरव्ही मे तैनात पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं वाहन चालक उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने परीक्षा केन्द्रों का किया निरीक्षण

समवेत शिखर संवाददाता

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2026 अंतर्गत आज जिले के परीक्षा केन्द्र क्रमांक 75 में अंग्रेजी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हुई।

परीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं जिला शिक्षा अधिकारी डॉ दिनेश झा द्वारा संयुक्त रूप से शासकीय बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अम्बिकापुर तथा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर, अम्बिकापुर परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा व्यवस्था, गोपनीय सामग्री की सुरक्षा एवं परीक्षार्थियों की बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने सभी परीक्षा केन्द्रों में सुचारू रूप से संचालित करने एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश।

वनांचल क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार, सभी वर्ग व क्षेत्रों का समावेश, छत्तीसगढ़ का तीसरा बजट विकसित भारत की ओर अग्रसर : विधायक

समवेत शिखर संवाददाता

पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित बजट को प्रदेश के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी की दूरदर्शी सोच के साथ प्रस्तुत इस बजट वनांचल क्षेत्रो को विशेष प्राथमिकता दी गई है। जिससे वनांचल क्षेत्रो को विकास की नई रफ्तार मिलेगी।बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत की गई है और आज के बजट में बस्तर व सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं की प्रतिभा को मंच देने की दिशा में सराहनीय पहल है। इससे ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

पत्थलगांव विधायक एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय ने बजट पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य,शिक्षा,कृषि,अधोसंरचना क्षेत्रो के साथ साथ युवाओ,महिलाओ व किसानों के साथ साथ जनजातीय विकास पर विशेष फेकस किया गया है कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट में सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है।उन्होंने कहा कि यह बजट विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कारगार साबित होगा यह बजट वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तैयार किया गया है,जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से न केवल सरगुजा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी।इस तीसरे बजट ने साफ कर दिया कि हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे है।

विधायक व सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय ने कहा कि आज के बजट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की घोषणा को साकार करते सरगुजा विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये किया जाना क्षेत्र के लिए अत्यंत सुखद और ऐतिहासिक निर्णय है। इससे आधारभूत संरचना, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के नए अवसरों को गति मिलेगी। सरगुजा प्राधिकरण की उपाध्यक्ष होने के नाते इस हेतु मैं मुख्यमंत्री जी व वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।

बालक आश्रम मसनियाखुर्द बना प्रदेश का प्रेरणा विद्यालय

एक शिक्षक के संकल्प से बदली तस्वीर, बालक आश्रम मसनियाखुर्द बना उत्कृष्टता और नवाचार की मिसाल

समवेत शिखर संवाददाता

सक्ती। सक्ती जिले के सुदूर वनांचल में पहाड़ियों की गोद में स्थित विकासखंड सक्ती अंतर्गत ग्राम मसनिया कला के आश्रित ग्राम मसानियाखुर्द में अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम मसनियाखुर्द आज केवल एक विद्यालय नहीं, बल्कि सफलता की एक मिसाल बन चुका है। जब प्रधान पाठक शैलकुमार पांडेय ने यहाँ कार्यभार संभाला, तब यह आश्रम संसाधनों की भारी कमी और स्टाफ की अनुपलब्धता से जूझ रहा था। लेकिन एक शिक्षक के दृढ़ संकल्प और 'नवाचार' की सक्ती ने मात्र छह महीनों के भीतर यहाँ की शैक्षणिक, भौतिक और रचनात्मक तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक अकेले शिक्षक के रूप में विभागीय निर्देशों और स्वयं की प्रेरणा से उन्होंने इस आश्रम का कायाकल्प किया, जिसके परिणामस्वरूप आज यह न केवल सक्ती जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए एक 'प्रेरणा विद्यालय' के रूप में उभरा है।

इस आश्रम की बढ़ती ख्याति का ही प्रमाण है कि यहाँ अब रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और कोरबा जैसे पड़ोसी जिलों के छात्र भी बड़े चाव से पढ़ने आ रहे हैं। इस सफलता के पीछे विद्यालय का वह आधुनिक और रचनात्मक परिवेश है, जहाँ पुस्तकालय, खिलौना घर, डिजिटल कक्षा और किचन गार्डन जैसी सुविधाएँ बच्चों को किताबी ज्ञान से परे व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करती हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का आलम यह है कि 'एक छात्र ङ्क एक पेड़' मुहिम के तहत पूरा परिसर आज हरा-भरा और प्रेरणादायक बन चुका है। विद्यालय की इस अद्वितीय उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है, जहाँ तमिलनाडु द्वारा आयोजित 'ग्रीन डे' कार्यक्रम में देशभर के बड़े विश्वविद्यालयों के बीच इस प्राथमिक स्तर के आश्रम ने अपनी भागीदारी दर्ज कर गौरव हासिल किया।

आज स्थिति यह है कि निजी स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थी भी यहाँ की गतिविधियों, जैसे 'कबाड़ से जुगाड़' और विज्ञान शिक्षण को देखने के लिए भ्रमण पर आते हैं। आश्रम मसनियाखुर्द की इस सफलता को देखते हुए, 'हुनर के झोला' कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 10 अन्य विद्यालयों को भी इसी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और समर्पण गहरा, तो सीमित संसाधनों में भी शिक्षा के मंदिर को समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र बनाया जा सकता है। आज यह आश्रम बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ-साथ पूरे जिले के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुका है।

दो दिवसीय उन्नत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

समापन अवसर पर कलेक्टर हुए शामिल, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र किए वितरित

समवेत शिखर संवाददाता

सक्ती। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित आरएएमपी (रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी भावसर फाउंडेशन द्वारा होटल रैन बसेरा सक्ती में दो दिवसीय उन्नत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के समापन अवसर में कलेक्टर अमृत विकास तोपनो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं कौशल का उपयोग कर सफल उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा एवं उभरते उद्यमियों को शासकीय प्रोत्साहन योजनाओं, औद्योगिक नीतियों, वित्तीय प्रबंधन, विधिक प्रावधानों तथा विपणन रणनीतियों से संबंधित व्यवहारिक जानकारी प्रदान कर उनकी उद्यम क्षमता को सशक्त बनाना था। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों एवं संभावित व्यवसायियों ने प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

दो दिवसीय प्रशिक्षण में प्रमुख प्रशिक्षक सीए अरिहंत जैन द्वारा व्यवसायिक इकाइयों के प्रकार, अनुबंध एवं कानूनी दस्तावेजीकरण, नवीन औद्योगिक नीति, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के महत्वपूर्ण प्रावधानों, वित्तीय अनुशासन तथा व्यवसाय योजना निर्माण जैसे विषयों पर सरल एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रतिभागियों ने सत्रों को अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बताया। कार्यक्रम के समापन के दौरान अभिषेक सिंह, जोनल हेड, भावसर फाउंडेशन ने सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों एवं जिला उद्योग केंद्र के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के कौशल उन्नयन कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।